



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2007/ज्येष्ठ 18, 1929

No. 124]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2007/JYAISTHA 18, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2007

केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5)

फाइल सं. 416-1/2007-एफएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “एक्सेस सरलीकरण” से अभिप्रेत है केबल लैंडिंग स्टेशन पर अनिवार्य सुविधाओं (जिनमें समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं) के लिए, यथास्थिति, एक्सेस अथवा अंतरसंयोजन;
- (ख) “एक्सेस सरलीकरण प्रभारों” से अभिप्रेत है, समुद्री केबल क्षमता के किसी स्वामी अथवा समुद्री केबल क्षमता धारण करने वाले कंसोर्टियम के किसी सदस्य से प्रयोग के अलोप्य अधिकार के आधार पर अथवा अल्पावधि पट्टा आधार पर अर्जित क्षमता के अंतरसंयोजन अथवा एक्सेस के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामी को पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय कोई प्रभार;
- (ग) “अधिनियम” से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;
- (घ) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) "बैकहॉल सर्किट" से अभिप्रेत है कोई घरेलू दूरसंचार सर्किट जो किसी केबल लैंडिंग स्टेशन को इसके परिसरों में पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की अवसंरचना अथवा उपस्कर से जोड़ता है;

(च) "केबल लैंडिंग स्टेशन" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है—

- (i) जिस पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता बैकहॉल सर्किट से संपर्क योग्य है;
- (ii) जिस पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता कि एक्सेसिंग के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबलें तट पर उपलब्ध हैं; और ऐसे स्थान जिसमें शामिल हैं ऐसे भवन जिनमें बैकहॉल सर्किटों से जुड़ने के लिए समुद्री केबल के तटवर्ती छोर और उपस्कर निहित है;

(छ) "केबल लैंडिंग स्टेशन-रेफेरंस इंटरकनेक्शन ऑफर" से अभिप्रेत है केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा की गई कोई ऑफर जिसमें विनियम 3 के उप विनियम (3) के अधीन प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रकाशित एक्सेस सरलीकरण और उपस्कर के सह-स्थान (जिसमें अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल की संपर्कयोग्य प्रणाली के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों हेतु लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं) के निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट हैं;

(ज) "सह-स्थान सुविधाओं" से अभिप्रेत है समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन पर सुविधाएं (जिनमें भवन स्थान, बिजली, पर्यावरण सेवाएं, सुरक्षा और स्थल अनुरक्षण शामिल हैं) जोकि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा ऐसे स्वामी के केबल लैंडिंग स्टेशन को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करने के लिए (जिसमें सह-स्थान उपस्कर की स्थापना शामिल है) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को प्रदान की जाती है।

(झ) "सह-स्थान प्रभारों" से अभिप्रेत हैं प्रयोग की गई सुविधाओं के प्रकार के आधार पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय प्रभार; एक्सेस प्राप्तकर्ता होने के नाते ऐसे पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपस्कर को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के परिसरों पर स्थापित करने के लिए, जो इसके केबल लैंडिंग स्टेशन को एक्सेस प्रदान करता है, और इसमें उक्त प्रयोजनों के लिए स्थान, बिजली आपूर्ति, भौतिक सुविधाओं की एक्सेसिंग, सह-स्थान जगह के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रभार शामिल हैं।

(ञ) "सह-स्थान लीड-टाइम" से अभिप्रेत है पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को सह-स्थान जगह उपलब्ध कराने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा लिया गया समय;

(ट) "क्षमता स्वामी" से अभिप्रेत है एक कोई अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार वाहक अथवा विदेशी वाहक अथवा भारतीय अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक जो भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल लैंडिंग की क्षमता का स्वामित्व रखता है;

(ठ) "पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था" से अभिप्रेत है —

- (i) कोई अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, जो इस प्रकार कार्य करने का लाइसेंस धारण करता है, तथा, जिसे लाइसेंस के अधीन भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबल सिस्टम लैंडिंग में अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है; अथवा

(ii) एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो इस प्रकार कार्य करने के लिए वैध अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति अथवा लाइसेंस धारण करते हैं, तथा, जिन्हें लाइसेंस के अधीन भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबल सिस्टम लैंडिंग में अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ड) "ग्रूमिंग सेवा" से अभिप्रेत है ऐसे स्थान अथवा बिंदु पर समुद्री केबल से उच्च क्षमता के आउटपुटों का विखण्डन जिन पर ये पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बैकहॉल सर्किटों के कनेक्शन के लिए निम्न क्षमता वाले चैनलों में समाप्त होते हैं;

(ढ) "अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक" से अभिप्रेत है कोई सेवा प्रदाता अथवा प्रचालक जिसे अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने हेतु इस प्रकार कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है;

(ण) "प्रयोग का अलोप्य अधिकार" से अभिप्रेत है संदर्भ क्षमता का प्रयोग करने का अधिकार—

(i) दीर्घावधि पट्टे पर ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए समुद्री केबल प्रभावी प्रयोग में रहती है;

(ii) जो क्षमता स्वामी तथा किसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बीच किए गए किसी करार के अंतर्गत अर्जित किया गया हो (जिसमें उपस्कर, फाइबर अथवा क्षमता शामिल है);

(iii) जिसके संबंध में उपगत अनुरक्षण लागत इस खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट करार की वैधता अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में देय बन जाती है;

(त) "लाइसेंस" से अभिप्रेत है प्रदत्त अथवा प्रभावी ऐसा लाइसेंस जैसेकि यह भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) तथा भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अंतर्गत प्रदान किया गया है;

(थ) "प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों" से अभिप्रेत है वार्षिक प्रभार—

(i) जो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देय है;

(ii) जो ऐसे स्वामी के केबल लैंडिंग स्टेशन की क्षमता को एक्सेस करने के लिए सुविधाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए हैं;

(द) "संदर्भ क्षमता" से अभिप्रेत है अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता, —

(i) समुद्री केबल प्रणाली में, जो भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन पर लैंड करती है;

(ii) जो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा अर्जित अथवा लीज की गई है;

(iii) जो समुद्री केबल प्रणाली के स्वामी अथवा समुद्री केबल प्रणाली के कंसोर्टियम के किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा क्रियाशील की गई है;

(ध) "विनियमों" से अभिप्रेत है केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं (जिसमें समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं शामिल हैं) हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007;

- (न) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (प) "निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल" से अभिप्रेत है कोई समुद्री केबल जिसकी भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल लैंडिंग क्षमता है;
- (फ) "केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी" से अभिप्रेत है कोई सेवा प्रदाता जो भारत में समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी है और उसका संचालन करता है तथा जिसे अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।
- (ब) "वास्तविक सह-स्थान" से अभिप्रेत है —
- (i) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का स्थान, जोकि केबल लैंडिंग स्टेशन के बाहर है, चाहे वह ऐसे स्थान के साथ ही है अथवा दूरवर्ती है;
 - (ii) ऐसा स्थान जिस पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने उपस्कर को स्थापित कर सकेगी ताकि केबल लैंडिंग स्टेशन से उप-समुद्री केबल क्षमता को एक्सेस किया जा सके;
- (भ) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए तथा अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें, यथास्थिति, क्रमशः अधिनियम अथवा नियमों अथवा अन्य विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय II

केबल लैंडिंग स्टेशन तथा संबंधित अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस

3. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन तथा संबंधित अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस का प्रावधान — (1) प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी अपने प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंध में, —
- (क) अपने केबल लैंडिंग स्टेशन पर, उचित तथा गैर-भेदभावपूर्ण निबंधन और शर्तों पर, किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता को एक्सेस करने का अनुरोध करने वाले किसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक्सेस प्रदान करेगा;
 - (ख) भारत में इसके केबल लैंडिंग स्टेशन पर इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप ऐसी निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल लैंडिंग अंतरसंयोजित करेगा;
 - (ग) किसी सेवा प्रदाता को, जिसे लाइसेंस के अंतर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, अपने केबल लैंडिंग स्टेशन पर समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं प्रदान करेगा;

(घ) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्राधिकरण को इसके अनुमोदन के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें एक्सेस सरलीकरण और सह-स्थान सुविधाओं, जिनमें इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप विनिर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए इसके केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव" कहा गया है) शामिल हैं, के निबंधन एवं शर्तें अंतर्निहित होंगी -

परंतु यह कि ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के मामले में जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अस्तित्व में आता है, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के अस्तित्व में आने की तारीख को अथवा उससे पूर्व, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के संदर्भ में केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव प्राधिकरण को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) सह-स्थान प्रभारों सहित प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को इसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को उप-विनियम (1) के अंतर्गत इसके प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर अनुमोदित करेगा -

परंतु यह कि यदि प्राधिकरण की यह राय है कि दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं अथवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, अथवा दूरसंचार क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करने, उसे प्रोत्साहन देने अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में परिवर्धन करने की आवश्यकता है, अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है, तो वह केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंधित स्वामी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे स्वामी से उसके द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव को परिवर्धित करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा स्वामी ऐसे परिवर्धन करेगा और परिवर्धनों के लिए अपेक्षा की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे परिवर्धनों को अंतर्विष्ट करने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी, प्राधिकरण द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर तथा प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी अन्य रीति से, प्रकाशित करेगा तथा उसकी एक प्रति इस आशय की पुष्टि के साथ कि ऐसा प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप तथा इस उप-विनियम में निर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया गया है, प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

(5) केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी, जो उप-विनियम (4) के अधीन प्रकाशित अपने केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में कोई परिवर्धन करने का इच्छुक है, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में ऐसे सभी परिवर्धनों को प्राधिकरण की पूर्व-अनुमति के लिए प्रस्तुत करेगा।

(6) इन विनियमों के सभी प्रावधान, जो केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए लागू होते हैं, उप-विनियम (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के परिवर्धनों पर यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

4. केबल लैंडिंग स्टेशन के एक्सेस सरलीकरण तथा संबद्ध अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा आवेदन - (1) किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता को एक्सेस करने का इच्छुक प्रत्येक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था एक्सेस सरलीकरण के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को पंजीकरण शुल्क के साथ, जोकि ऐसी संस्था द्वारा देय एक्सेस सरलीकरण प्रभारों के बदले में बाद में समायोजित किया जाएगा, अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन करेगा, जिसमें निम्नलिखित भी संलग्न होंगे, अर्थात्-

(क) अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालन के रूप में कार्य करने के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लाइसेंस करार की एक प्रति अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए वैध अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति के साथ लाइसेंस करार की एक प्रति, जैसा भी मामला हो;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा एक प्रमाण-पत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि इसे अन्तरराष्ट्रीय गेटवे के प्रचालन के लिए भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अथवा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण, यदि विधि के अंतर्गत कोई हो, द्वारा अनुमति अथवा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) समुद्री केबल के स्वामी अथवा समुद्री केबल प्रणाली का स्वामित्व रखने वाले कंसोर्टियम के सदस्य अथवा संबंधित केबल प्रणाली में क्षमता स्वामी से, संयुक्त रूप से अथवा भिन्न-भिन्न, एक पुष्टि जिसमें यह कहा गया हो कि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था संदर्भ क्षमता की बिक्री अथवा पट्टे के लिए उसके अथवा उनके साथ करार अथवा समझौता ज्ञापन कर चुकी है।

(घ) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि यह संदर्भ क्षमता का उपयोग इसके लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुरूप ही करेगी।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट पुष्टि में, अन्य बातों के साथ, निम्न निर्दिष्ट किया जाएगा -

(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा प्रयोग के विलोप्य अधिकार के रूप में अथवा वार्षिक पट्टे के आधार पर अर्जित की गई अथवा अर्जित करने के लिए सहमत इकाइयों की संख्या;

(ख) उप-विनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट संदर्भ क्षमता के पट्टे की अवधि जिसे प्रयोग के विलोप्य अधिकार के रूप में अथवा वार्षिक पट्टे के आधार पर अर्जित किया जाना है अथवा अर्जित किए जाने के लिए सहमति है;

(ग) निम्न से संबंधित तकनीकी जानकारी -

- (i) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा प्रासंगिक समुद्री केबल प्रणाली में अर्जित की गई अथवा अर्जित करने के लिए सहमत संदर्भ क्षमता का स्लॉट आवंटन;
- (ii) अर्जित अथवा अर्जित किए जाने के लिए सहमत क्षमता का धारक पदनाम;
- (iii) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा संदर्भ क्षमता के परीक्षण की अंतिम तारीख अथवा प्रत्याशित तारीख।

5. विनियम 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा पुष्टि — (1) केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी, एक्सेस सरलीकरण के लिए आवेदन तथा विनियम 4 के अधीन अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्राप्त होने के बाद से दस दिन की अवधि के भीतर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को ऐसा एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षण के ब्यौरे तथा एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने की उसकी योग्यता की उसकी पुष्टि भेजेगा।

(2) यदि किसी वैध कारण से केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के लिए, यथास्थिति, एक्सेस सरलीकरण पद्धति अथवा उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट, किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षण का अनुपालन करना व्यवहार्य न हो, तो ऐसा स्वामी, विनियम 4 के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक्सेस सरलीकरण तथा किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षण के लिए वैकल्पिक प्लान के बारे में कारणों के लिखित विवरण के साथ सूचित करेगा तथा ऐसा प्रक्रिया न अपनाने या परीक्षण न करने के वैध कारणों के बारे में भी बताएगा।

6. एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने के लिए कोई करार करना — (1) एक्सेस सरलीकरण के लिए पुष्टि की प्राप्ति के पश्चात्, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, ऐसी पुष्टि की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ एक्सेस सरलीकरण करार करेगा —

परंतु यह कि यदि विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (i) अथवा (ii) के अंतर्गत आने वाला अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व किसी केबल लैंडिंग स्टेशन के किसी स्वामी के साथ कोई करार करता है, तथा ऐसे स्वामी का केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, तो ऐसा स्वामी विनियम 3 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत उक्त प्रस्ताव के प्रकाशन के पश्चात्, इन विनियमों के अनुरूप एक्सेस सरलीकरण के लिए आवेदन करने के लिए, यथास्थिति, ऐसे अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता को एक विकल्प देगा।

(2) यदि किसी केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था उप-विनियम (1) के अंतर्गत करार करने में असफल रहता है, तो उस मामले में, अधिनियम की धारा 14 क के उपबंधों पर प्रभाव डाले बिना, दोनों, संयुक्त रूप से, किसी भी समय, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट करार को करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्राधिकरण को अनुरोध कर सकेंगे।

(3) उप-विनियम (2) में निहित किसी भी बात को पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था और केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन प्रदत्त कानूनी अधिकारी को हटा लिया जाना नहीं समझा जाएगा और उनमें से कोई भी, सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान उस उप-विनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन उन्हें प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

(4) उप-विनियम (2) में निहित कोई भी बात किसी ऐसे विषय या मुद्दे पर लागू नहीं होगी जिसके संबंध में —

(क) किसी न्यायालय या अधिकरण में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम या अन्य कानून के अधीन कोई कार्यवाही लंबित है; अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण, यथास्थिति, द्वारा पहले कोई डिक्री या निर्णय या आदेश पारित किया जा चुका है।

7. संदर्भ क्षमता की एक्सेस के लिए मांग — (1) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, विनियम 6 के अंतर्गत करार किए जाने के पांच दिन के भीतर संदर्भ क्षमता के लिए एक्सेस सरलीकरण प्राप्त करने हेतु अनुसूची के भाग II में यथानिर्दिष्ट ऐसे शुल्कों एवं प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत देय शुल्कों तथा प्रभारों का भुगतान प्राप्त होने पर केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, प्रयोग के विलोप्य अधिकार के रूप में अथवा करार में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक पट्टा आधार पर अर्जित की जाने वाली अथवा अर्जित किए जाने के लिए सहमत इकाइयों की संख्या पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा की गई पुष्ट मांग के रूप में विचार करेगा।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट पुष्ट मांग पर विचार करने के तुरंत पश्चात् पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए एक्सेस सरलीकरण के प्रावधान की कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

8. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बैकहॉल सर्किट का प्रावधान सुनिश्चित करना — (1) प्रत्येक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था निम्नलिखित से बैकहॉल सर्किट के लिए विनियम 6 के उप-विनियम (1) के अधीन करार करने के पश्चात् दस दिनों के भीतर बैकहॉल सर्किट की व्यवस्था करेगा—

(क) केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी; या

(ख) कोई सेवा प्रदाता जिसे बेसिक सेवा या सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा या अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है,

जिससे कि वह केबल लैंडिंग स्टेशन और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के परिसरों के बीच बैकहॉल सर्किट तैयार कर सके।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण पद्धति के अनुसार आवश्यक परीक्षण करेंगे ताकि बैकहॉल सर्किट संदर्भ क्षमता के प्रावधान के लिए किए जाने वाले परीक्षणों से पूर्व अंतरसंयोजन के लिए तैयारी की स्थिति में रहें।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उप-विनियम (1) के अधीन बैकहॉल सर्किट के प्रावधान के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर उप-विनियम (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था और सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन का सरलीकरण करेगा।

9. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा अर्जित किए जाने वाली प्रस्तावित संदर्भ क्षमता का परीक्षण — (1) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, केबल लैंडिंग स्टेशन के बैकहॉल सर्किट का सफल परीक्षण करने के पश्चात् संदर्भ क्षमता हेतु एक्सेस सरलीकरण के लिए सभी आवश्यक चरणों को पूरा करेंगे तथा ऐसे चरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होगा—

(क) लिंको का परीक्षण;

(ख) ऐसे स्वामी के केबल लैंडिंग स्टेशन पर अथवा वास्तविक सह-स्थान पर सह-स्थित सेवा प्रदाता के बैकहॉल सर्किट अथवा उपस्कार की संदर्भ क्षमता का अंतरसंयोजन।

(2) विनियम 4 के अधीन आवेदक होने के नाते, केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, दस दिन अथवा उनके द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अथवा भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन से दूरवर्ती छोर अथवा अन्य देशों के समुद्री केबल स्टेशन तक संदर्भ क्षमता के प्रावधान के लिए परीक्षण पद्धति के अनुसार आवश्यक परीक्षण संचालित करेंगे।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी—

(क) उप-विनियम 2 में निर्दिष्ट कदमों को उठाने के पश्चात् संदर्भ क्षमता का नियंत्रण करने के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक सूचना भेजेगा;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था से सभी आवश्यक भुगतान प्राप्त होने पर ऐसी संस्था को संदर्भ क्षमता तत्काल, परंतु ऐसे भुगतान की प्राप्ति के दो दिन के अपश्चात्, वितरित करेगा और यथाअधिप्राप्त संदर्भ क्षमता को घोषित करेगा।

10. एक्सेस सरलीकरण प्रभार तथा भुगतान निबंधन — (1) किसी केबल लैंडिंग स्टेशन पर लैंडिंग सुविधाएं एक्सेस करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची के भाग II में यथानिर्दिष्ट एक्सेस सरलीकरण प्रभार—

(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देय होंगे;

(ख) एक्सेस के प्रावधान में शामिल तथा प्रणाली पूर्ण क्षमता के लिए वितरित नेटवर्क अवयवों की लागत के आधार पर अवधारित किए जाएंगे।

(2) एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान के अधीन, प्रयोग के विलोप्य अधिकार की अवधि के दौरान अथवा किसी वार्षिक पट्टे के आधार पर, यथास्थिति प्रवृत्त रहना जारी रहेगी।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को केबल लैंडिंग स्टेशन पर ग्रूनिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा।

11. क्षमता उन्नयन तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा क्षमता उन्नयन प्रभारों का भुगतान — यदि केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के एक्सेस सरलीकरण के लिए क्षमता के उन्नयन को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, ऐसे उन्नयन के लिए अनुरोध प्राप्त होने, तथा विनियम 4 के अधीन एक आवेदक होने के माते पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था से ऐसे उन्नयन के लिए प्रभारों के भुगतान पर, इन विनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारस्परिक आधार पर सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार, जिनमें ऐसे उन्नयन के लिए समय-सीमा भी शामिल है, उन्नयन का सरलीकरण करेगा।

12. रद्दकरण प्रभार — (1) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में उल्लिखित इकाइयों की संख्या को अर्जित करने में असफल रहती है, चाहे ऐसा विनियम 7 में उल्लिखित प्राधिकार के वापस लेने अथवा करार के निरस्त होने के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से हुआ हो, तो इस प्रकार अर्जित न की गई इकाइयों के लिए रद्दकरण प्रभार ऐसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देय होगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रद्दकरण प्रभार ऐसे होंगे, जैसेकि अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट किये गये हैं।

13. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण का समापन अथवा विच्छेदन— (1) केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण को समाप्त किया जा सकेगा—

(क) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था समाप्ति अथवा विच्छेदन के माध्यम से वैध लाइसेंस धारण करना समाप्त कर देती है;

(ख) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा समुद्री केबल प्रणाली के धारक अथवा समुद्री केबल प्रणाली कंसोर्टियम के किसी सदस्य अथवा संबंधित केबल कंसोर्टियम से प्रयोग के अलोप्य आधार पर अथवा किसी वार्षिक पट्टे के आधार पर, यथास्थिति, संदर्भ क्षमता अर्जित करने की व्यवस्था समाप्त हो जाती है।

(2) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय तथा भुगतानयोग्य वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार, ऐसे प्रभारों के भुगतान योग्य होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक, असंदत्त रहता है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को प्रदान की गई एक्सेस सुविधा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को ऐसे विच्छेदन के लिए 5 दिन से अन्यून का लिखित नोटिस देने के पश्चात् समाप्त कर सकेगा और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय ऐसे प्रभारों का भुगतान कर देने के बाद तत्काल एक्सेस सुविधाओं की पुनःबहाली कर दी जाएगी।

14. एक्सेस सुविधाओं की पुनःबहाली - (1) यदि विनियम 13 के अधीन पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का लाइसेंस समाप्त अथवा विच्छेदित कर दिया जाता है परंतु उसे बाद में पुनःबहाल कर दिया जाता है, तो एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था विनियम 13 के अधीन लाइसेंस के ऐसे समापन या विच्छेदन के कारण समाप्त किए जाने पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा, यथास्थिति, एक्सेस सुविधाएं पुनःसंयोजित अथवा पुनःबहाल करने के प्रयोजनार्थ उपगत सभी लागतों का पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को भुगतान करने पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था बहाल की जा सकेगी, तथा ऐसे पुनःसंयोजन अथवा पुनःबहाली प्रभार वे होंगे जैसाकि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा तय किए जाएं अथवा जिसके न होने पर वे अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट लागतों के अनुरूप होंगे।

(2) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का कोई प्राधिकार अथवा इसके द्वारा समुद्री केबल प्रणाली से अथवा समुद्री केबल प्रणाली कंसोर्टियम के सदस्य से अथवा संबंधित समुद्री केबल कंसोर्टियम से प्रयोग के विलोप्य अधिकार अथवा पट्टे पर संदर्भ क्षमता अर्जित करने के लिए की गई कोई व्यवस्था या तो वापस ले ली गई हो अथवा निरस्त कर दी गई हो परंतु उसे बाद में पुनःबहाल कर दिया गया हो, तो एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था, यदि यह ऐसे वापस लिए जाने अथवा निरस्त किए जाने के कारण विच्छेदित कर दी गई थी, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा, यथास्थिति, पुनः संयोजित अथवा पुनःबहाल करने के प्रयोजनार्थ उपगत सभी लागतों का पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को भुगतान करने पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था बहाल की जा सकेगी, तथा ऐसे पुनःसंयोजन अथवा पुनःबहाली प्रभार वे होंगे जैसाकि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा तय किया जाए अथवा जिसके न होने पर वे अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट लागतों के अनुरूप होंगे।

अध्याय III

सह-स्थान स्थल तथा सह-स्थान जगह

15. सह-स्थान जगह के प्रावधान के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा आवेदन— (1) प्रत्येक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, जो विनियम 4 के अंतर्गत किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग पर सह-स्थान जगह के लिए आवेदन करती है, उस समय अनुसूची के भाग IV में निर्दिष्ट प्रपत्र में केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को, साथ-साथ, दूसरा आवेदन करेगी, यदि उसके द्वारा ऐसी सह-स्थान जगह ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी से किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग के लिए अपेक्षित हो, जिसके साथ वह निम्नलिखित संलग्न करेगी, अर्थात् -

(क) उस सह-स्थान पर उपस्कर की ले-आउट योजना जहां पर सह-स्थान जगह के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग का उद्देश्य;

(ग) स्थापना के लिए प्रस्तावित सह-स्थान उपस्कर

(घ) स्थान एवं विद्युत आवश्यकताओं के विवरण

(ङ) सह-स्थान उपस्कर की फ्लोर लोडिंग

(च) अपेक्षित ट्रांसमिशन टाई-केबल का विनिर्देशन

(छ) प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार

(ज) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का पता, दूरभाष संख्या, फैक्स और ई-मेल जिस पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा संप्रेषण किए जाने हैं:

(झ) उपस्कर के सह-स्थान के लिए कोई अन्य अपेक्षा।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के दस दिन के भीतर पावती देगा तथा उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुरोध करने वाली पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विषय में सूचित करेगा।

(3) यदि किन्हीं वैध कारणों से केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के लिए उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह-स्थान उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसा स्वामी, उप-विनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को, ऐसी अव्यवहार्यता और उसके वैध कारणों के बारे में लिखित में सूचित करेगा। कारणों के लिखित वक्तव्य के साथ, सूचित करेगा।

(4) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उप-विनियम (1) के अंतर्गत पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार करेगा, यदि एक्सेस प्राप्तकर्ता एक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था नहीं है अथवा उसे अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति अथवा लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(5) उप-विनियम (2) के अधीन केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात् पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, ऐसी पुष्टि की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ सह-स्थान पट्टा करार करेगी।

16. सह-स्थान प्रभार तथा भुगतान निबंधन — (1) सह-स्थान प्रभार, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा, जिसे केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा सह-स्थान उपलब्ध कराया गया है,

विनियम 15 के उप-विनियम (5) के अधीन करार किए जाने के पांच दिन के भीतर, केबल लैंडिंग स्टेशन के ऐसे स्वामी को देय होंगे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सह-स्थान प्रभार ऐसे होंगे जैसे विनियम 3 के उप-विनियम (4) के अधीन प्रकाशित केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में शामिल किए गए थे।

परंतु, यह कि प्राधिकरण, अधिनियम के अंतर्गत इसके द्वारा बनाए गए किसी विनियम द्वारा, ऐसे सह-स्थान प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जोकि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के वर्ग अथवा वर्गों द्वारा देय होंगे तथा ऐसे मामले में सह-स्थान प्रभारों का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, जैसाकि अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट किया गया है, इन विनियमों के अंतर्गत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अनुसूची के भाग III के उप पैरा ख के अधीन विनिर्दिष्ट सह-स्थान सेवाओं के प्रावधान हेतु समयावधि के होते हुए भी, सह-स्थान प्रभार, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा उनके द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई समय-सीमा के अनुसार देय होंगे तथा जहां ऐसी समय-सीमा की सहमति नहीं बन सकी है, वहां सह-स्थान प्रभारों का ऐसे अंतरालों पर भुगतान किया जाएगा, जैसाकि उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट हैं।

(4) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर तथा सभी प्रभारों की प्राप्ति पर और इन विनियमों के अधीन अन्य अपक्षाओं की पूर्ति होने पर, ऐसी भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को, जिसने ऐसा आवेदन किया है, केबल लैंडिंग स्टेशन पर, ऐसी सह-स्थान सुविधा के लिए समय-सीमा सहित पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार सह-स्थान सुविधा उपलब्ध कराएगा।

17. वैकल्पिक सह-स्थान जगह का आवंटन — (1) यदि स्थान की कमी अथवा किसी अन्य वैध कारण से केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा अनुरोध किए गए वास्तविक सह-स्थान को प्रदान करने में असमर्थ है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी वास्तविक सह-स्थान के विकल्प देने के लिए युक्तिसंगत उपाय करेगा ताकि ऐसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था एक्सेस सुविधा प्राप्त करने में सफल हो सके:

परंतु यदि केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह-स्थान जगह प्रदान करने में असमर्थ है और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था एक वास्तविक सह-स्थान जगह की व्यवस्था करने में असफल रहती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी वास्तविक सह-स्थान के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन के सह-स्थान और अंतरसंयोजन के लिए वैकल्पिक स्थल से संबंधित प्रभार पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे।

(3) यदि केबल लैंडिंग स्टेशन पर स्थान के अभाव के कारण अथवा किन्हीं अन्य वैध कारणों से कोई पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा किसी वास्तविक सह-स्थान सुविधा प्रदान की जाती है, तो ऐसे मामले में केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन में अंतरसंयोजन केबल चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित अवयव (जिसमें

भवन के भीतर डक्ट शामिल है) उपलब्ध कराएगा जिसके लिए प्रभार पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय होंगे व वहन किए जाएंगे।

(4) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वास्तविक सह-स्थान जगह से केबल लैंडिंग स्टेशन तक दूरसंचार संपर्क की व्यवस्था करेगी, जिसकी लागत का वहन ऐसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा किया जाएगा।

18. अतिरिक्त सह-स्थान जगह तथा सह-स्थान उपस्कर — (1) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह-स्थान जगह में इसके किसी भी सह-स्थान उपस्कर को बदलने, परिवर्धित करने अथवा पुनः व्यवस्थित करने का आशय रखती है अथवा सह-स्थान जगह में अतिरिक्त सह-स्थान उपस्कर स्थापित करना चाहती है, तो यह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्धन, पुनःव्यवस्था अथवा अतिरिक्त सह-स्थान उपस्कर अथवा प्रतिस्थापन के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को लिखित में अनुरोध प्रस्तुत करेगी तथा केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के दस दिन के भीतर, ऐसे प्रतिस्थापन, परिवर्धन अथवा पुनःव्यवस्था के लिए अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत किए गए ऐसे अनुरोध के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से स्वीकृति की प्राप्ति होने पर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था समस्त प्रभारों का भुगतान करने तथा इस विनियमों के अधीन अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् सह-स्थान जगह में अपने किसी सह-स्थान उपस्कर को, यथास्थिति, परिवर्धित, पुनःव्यवस्थित अथवा प्रतिस्थापित करेगी अथवा सह-स्थान जगह में अतिरिक्त सह-स्थान उपस्कर स्थापित करेगी।

19. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह-स्थान उपस्करों की स्थापना— पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था जिसने विनियम 15 के उप-विनियम (5) के अधीन केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ करार किया है अनुसूची के भाग V में निर्दिष्ट सह-स्थान उपस्कर स्थापना एवं अनुरक्षण पद्धतियों के अनुरूप उसके तथा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हुए सह-स्थान जगह में अपने सह-स्थान उपस्कर स्थापित करेगी।

20. केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह-स्थान जगह के लिए वास्तविक एक्सेस हेतु प्राधिकार— यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अनुसूची के भाग VII में निर्दिष्ट प्रपत्र में इसके कार्मिकों के नामों को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को सूचित करेगी जो उन्हें सह-स्थान जगह पर एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करेगा और अनुसूची के भाग VI में निर्दिष्ट प्रपत्र में वास्तविक रूप से एक्सेस करने के लिए प्रमाणन जारी करेगी।

21. सह-स्थान को उप-पट्टे पर देने का प्रतिषेध — पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन और सह-स्थान स्थल पर सह-स्थान जगह के संदर्भ में पट्टा अथवा उप-किराएदारी नहीं कर सकेगी।

22. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन में समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली सह-स्थान जगह — (1) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह-स्थान जगह का प्रयोग केबल लैंडिंग स्टेशन में समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग के लिए किया जाएगा।

(2) सह-स्थान जगह पर स्थापित पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपस्करों का प्रयोग, निम्नलिखित के लिए किया जा सकेगा—

(क) बैकहॉल सर्किट का प्रावधान करने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर विनियम 8 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट बैकहॉल सर्किट प्रदाताओं अथवा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाओं के बीच अंतरसंयोजनों के लिए;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाओं के परिसरों या तथा प्वाइंट ऑफ प्रेजेस की संदर्भ क्षमता का विस्तार करने के लिए।

23. सह-स्थान जगह के पट्टे की समाप्ति — (1) सह-स्थान जगह के बंद हो जाने अथवा संदर्भ क्षमता के पट्टे की समाप्ति के मामले में, केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, यथास्थिति, ऐसे बंद होने अथवा संदर्भ क्षमता के पट्टे की समाप्ति से पूर्व छह माह से अन्यून अवधि का लिखित में, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को नोटिस देने के पश्चात् सह-स्थान जगह का पट्टा समाप्त कर सकेगा तथा सह-स्थान जगह के पट्टे की ऐसी समाप्ति नोटिस में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, सह-स्थान का पट्टा समाप्त कर सकेगा, यदि—

(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वैध लाइसेंस धारण करना समाप्त कर देती है अथवा लाइसेंस, भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था, शालीनता अथवा मर्यादा अथवा किन्हीं अन्य कारणों से ऐसे पट्टे की समाप्ति का निदेश देता है;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था विनियमों अथवा अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जारी निर्देशों के उल्लंघन में अथवा लाइसेंस के निबंधनों के उल्लंघन में सह-स्थान जगह का उपयोग करती है अथवा उसके उपयोग की अनुमति देती है;

(ग) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था इसे सह-स्थान उपस्करों को हटा लेती है अथवा त्याग देती है अथवा ऐसे स्थान को 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए निरर्थक रखती है;

(घ) सह-स्थान जगह इन विनियमों के अधीन सुविधाएं एक्सेस करने के प्रयोजन के लिए असुरक्षित अथवा अनुपयुक्त हो गई है;

परंतु यह कि केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी खंड (ख) से (ग) के अधीन सह-स्थान जगह के पट्टे को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक कि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को दस दिन के अन्यून अवधि का नोटिस न दे दिया गया हो।

(3) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति के पूर्व किए गए अनुरोध पर सह-स्थान जगह के पट्टे की समाप्ति होने पर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रकार देय होंगे, अर्थात् —

(क) सह-स्थान प्रभार जोकि छह माह से अनधिक की अवधि के लिए देय हो;

(ख) बकाया यथानुपात स्थल तैयारी कार्य—प्रभार।

(4) उप-विनियम (3) में अतिविष्ट उपबंधों के अधधीन, केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को दस दिन से अन्यून का नोटिस देकर, किसी भी समय, सह-स्थान जगह के पट्टे को समाप्त कर सकेगा यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था नब्बे (90) दिन के भीतर इसके सह-स्थान उपस्कर की स्थापना को पूर्ण करने में सफल रहती है।

(5) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, इसके युक्तिसंगत नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण, इसके सह-स्थान उपस्कर की स्थापना को पूर्ण करने में असफल रहती है, तो यह ऐसी परिस्थितियों की सूचना केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देगी जो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उसके सह-स्थान उपस्कर की स्थापना के लिए समय का युक्तिसंगत विस्तार प्रदान करेगा।

(6) यदि उप-विनियम (1) के अधीन पट्टे की समाप्ति पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था इसके सह-स्थान उपस्कर के प्रयोग को समाप्त करने तथा उस विनियम के अधीन इसके सह-स्थान उपस्कर को हटाने में असफल रहती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी सह-स्थान उपस्कर को हटा सकेगा तथा सह-स्थान जगह को इसकी वास्तविक स्थिति में पुनःबहाल करेगा।

(7) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की सह-स्थान जगह के पट्टे की अवधि पूरी होने अथवा समाप्ति पर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को, सह-स्थान उपस्कर को हटाने के पश्चात् (जिसमें सह-स्थान उपस्कर का निपटान भी शामिल है) उप-विनियम (6) के अधीन पुनःबहाली के लिए किए गए कार्य से जुड़ी हुई सभी युक्तिसंगत लागतों का भुगतान करेगी।

(8) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की सह-स्थान जगह के पट्टे की अवधि पूरी होने अथवा समाप्ति पर, सह-स्थान जगह के लिए प्रदान की गई कोई वास्तविक एक्सेस वापस ले ली जाएगी।

(9) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को पहले से समाप्त सह-स्थान सुविधाओं की पुनःबहाली अपेक्षित है तो वह इसके लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अनुरोध करे जो यथाशीघ्र पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए सह-स्थान सुविधाओं की पुनःबहाली के लिए युक्तिसंगत प्रयत्न तथा समस्त प्रयास करेगा।

(10) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात को, किसी सेवा गारंटी करार के लिए अथवा विनिर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल प्रणाली के निष्पादन पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा किसी अभ्यावेदन को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी पर बाध्यकारी होना नहीं माना जाएगा।

(11) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था किसी पुनःबहाली व्यवस्था के लिए, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो वैकल्पिक संप्रेषण माध्यम शामिल है, यथास्थिति, समुद्री केबल प्रणाली के स्वामी अथवा समुद्री केबल प्रणाली के सदस्य के साथ बातचीत कर सकेगा।

अध्याय IV

प्रकीर्ण

24. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सह-स्थान उपस्कर के एक दूसरे के निकटवर्ती स्थानों पर रखने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी का कोई दायित्व न होना—केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा इसके सह-स्थान उपस्कर को एक दूसरे के निकटवर्ती रखने के लिए किए गए युक्तिसंगत अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करेगा परंतु ऐसा अनुरोध इसके सह-स्थान उपस्कर के निकटवर्ती स्थापित करने के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा तथा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा आवंटित सह-स्थान और यथाअवधारित सह-स्थान उपस्कर की वास्तविक स्थापना अंतिम होगी।

25. सह-स्थान करार की अवधि — (1) सह-स्थान ढांचे के अंतर्गत पट्टे पर ली जाने वाली प्रत्येक सह-स्थान जगह के बारे में पक्षकारों के बीच करार उस तारीख से प्रारंभ होगा जिससे पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह-स्थान जगह के लिए प्रमारों की स्वीकार्यता के लिए अपनी पुष्टि करती है और उसके लिए भुगतान करती है तथा यह इस प्रकार प्रारंभ होने से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि जिसपर पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत हों, के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित सह-स्थान सुविधा की अवधि का नवीकरण केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा तभी किया जाएगा, यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था ने सह-स्थान प्रमारों के भुगतान में चूक नहीं की है अथवा इसने ऐसे करार की किसी निबंधन अथवा शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

26. प्रतिवेदन संबंधी अपेक्षाएं — विनियम 6 के अधीन किया गया एक्सेस सुविधा करार अथवा विनियम 15 के उप-विनियम (5) के अधीन किया गया सह-स्थान पट्टा करार अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बीच इन विनियमों के उपबंधों के अनुरक्षण में किए गए प्रत्येक अन्य करार, ऐसे करार किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

अनुसूची**केबल लैंडिंग स्टेशन—संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव
(सीएलएस—आरआईओ) का प्रपत्र**

[केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 के विनियम 3 को देखें]

भाग—I

अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर एक्सेस सरलीकरण का अनुरोध करने के लिए आवेदन प्रपत्र

(देखें विनियम 4)

मैसर्स (पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का नाम)
एतद्वारा नीचे उल्लिखित क्षमता के एक्सेस सरलीकरण के लिए अनुरोध करता है जो अनिवार्य सुविधाओं के एक्सेस सरलीकरण, जिसमें केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबल हेतु लैंडिंग सुविधाएं शामिल हैं, के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर अनिवार्य सुविधाओं (समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित) दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए "केबल लैंडिंग स्टेशन—संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस—आरआईओ) में प्रकाशित निबंधन और शर्तों के अध्वधीन है।

मैसर्स निम्नानुसार आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें —

1. कंपनी का नाम और उसका पता	
2. बिलिंग पता	
3. संपर्क व्यक्ति	
3.1 नाम:	
3.2 दूरभाष सं०:	
3.3 ई-मेल:	
3.4 फैक्स:	
4. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का ब्यौरा	
4.1 अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर	
4.2 इंटरनेट सेवा प्रदाता	
4.3 लाइसेंस संख्या	

4.4 लाइसेंस जारी करने की तारीख (कृपया यथा लागू लाइसेंसों और वैध गेटवे लाइसेंस की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
5. संदर्भ क्षमता के तकनीकी ब्यौरे (कृपया संबंधित जानकारी और ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराएं अथवा संलग्न करें)	
5.1 संदर्भ क्षमता ब्यौरा: गति (एसटीएम-1/एसटीएम-4/एसटीएम-16/एसटीएम-64 आदि)	
5.2 क्षमता इकाइयों की संख्या	
5.3 प्रयोग का विलुप्य अधिकार अथवा पट्टे पर देना	
5.4 अवधि (पट्टे पर देने के मामले में)	
6. समुद्री केबल की संदर्भ क्षमता के तकनीकी ब्यौरे:—	
6.1 केबल स्टेशन बैकहॉल पोर्ट ब्यौरे (क्षमता और टाइप—एसटीएम-1ई/एसटीएम-1ओ/ एसटीएम-4/एसटीएम-16/एसटीएम-64 आदि)	
6.2 समुद्री केबल प्रणाली क्षमता स्वामी द्वारा सौंपा गया कार्य, यदि उपलब्ध हो, (समुद्री केबल में स्लॉट अथवा फाइबर पेयर आवंटन, धारक का पदनाम, केबल प्रणाली स्वामी का आंतरिक आईडी आदि)	
6.3 बैकहॉल सर्किट परीक्षण की प्रस्तावित/अनन्तिम तारीख	
6.4 प्रस्तावित परीक्षण कार्यक्रम और संदर्भ क्षमता परीक्षण की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए कोई अन्य संबंधित तकनीकी जानकारी सहित केबल प्रणाली के स्वामी द्वारा जारी कार्य आदेश/दस्तावेज की प्रति	
6.5 एक छोर से दूसरे छोर तक परीक्षण (पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था और दूरवर्ती समुद्री केबल स्टेशन के बीच) कार्यक्रम और केबल लैंडिंग स्टेशन पर संदर्भ क्षमता की एक्सेस का प्रावधान करना।	

7. संदर्भ क्षमता स्वामी (यों)/समुद्री केबल क्षमता स्वामी (यों) के ब्यौरे (विनियम 4 के उप-विनियम (1) का खंड (ग) देखें)	
7.1 कंपनी का नाम और पता	
7.2 संपर्क व्यक्ति	
7.2.1 नाम:	
7.2.2 दूरभाष:	
7.2.3 ई-मेल:	
7.2.4 फैक्स:	
8. बैंकहॉल सर्किट प्रदाता (यों) (लोकल लूप सहित घरेलू संपर्क) के ब्यौरे	
8.1 कंपनी का नाम और पता	
8.2 संपर्क व्यक्ति	
8.2.1 नाम:	
8.2.2 दूरभाष:	
8.2.3 ई-मेल:	
8.2.4 फैक्स:	
9. पंजीकरण शुल्क भुगतान का ब्यौरा	
9.1 चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट सं०दिनांक रुपये (बैंक/शाखा) पर आहरित	
10. इस प्रपत्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (कृपया प्राधिकार संलग्न करें)	
11. अन्य कोई ब्यौरे जो दिए जाने अपेक्षित हैं किंतु जो इस प्रपत्र के क्र.सं. 1 से 9 तक में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक:

नाम:

हस्ताक्षर:

अधिकारिक मुहर:

भाग—II

(देखें विनियम, 3,7,10,12,14 और 16)

प्रभारों का ब्यौरा (1)		देय राशि (रुपयों में) (2)
1. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए एक्सेस सरलीकरण प्रभार		
प्रयोग के विलुप्य अधिकारों अथवा पंजीकृत पट्टे के आधार के मामले में एक्सेस सरलीकरण करार हो जाने पर देय प्रति इकाई क्षमता एक बारीय एक्सेस सरलीकरण प्रभार		
क्र०सं०	प्रति इकाई क्षमता	
(i)	एसटीएम-1	
(ii)	एसटीएम-4	
(iii)	एसटीएम-16	
(iv)	एसटीएम-64	
1.2 पट्टे के मामले में, एक्सेस सरलीकरण करार हो जाने पर देय प्रति इकाई क्षमता पर आवर्ती एक्सेस सरलीकरण प्रभार और उसके बाद प्रत्येक परवर्ती वर्ष की देय तारीख से पहले (प्रारंभ होने की तारीख का एक वर्ष हो जाने पर)। (प्रत्येक इकाई क्षमता के लिए केवल पहले तीन वर्षों अथवा यथालागू अवधि के लिए लागू)		
क्र०सं०	प्रति इकाई क्षमता	
(i)	एसटीएम-1	
(ii)	एसटीएम-4	
(iii)	एसटीएम-16	
(iv)	एसटीएम-64	
2. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) प्रभार		
2.1 एक्सेस सरलीकरण करार हो जाने पर देय प्रति इकाई वार्षिक प्रभार और उसके बाद प्रत्येक परवर्ती वर्ष की देय तारीख से पहले (प्रारंभ होने की तारीख का एक वर्ष हो जाने पर)।		
क्र०सं०	प्रति इकाई क्षमता	
(i)	एसटीएम-1	
(ii)	एसटीएम-4	
(iii)	एसटीएम-16	
(iv)	एसटीएम-64	
3. एक्सेस सुविधाओं के समाप्त होने अथवा विच्छेदन होने की स्थिति में प्रति इकाई क्षमता एक बारीय पुर्नबहाली प्रभार		
क्र०सं०	प्रति इकाई क्षमता	
(i)	एसटीएम-1	
(ii)	एसटीएम-4	
(iii)	एसटीएम-16	

(iv)	एसटीएम-64	
4. सहस्थान प्रभार — (कृपया मदों और उनके प्रभारों के अलग-अलग निर्दिष्ट करें जैसे—प्रति वर्ग फुट भवन स्थान प्रभार, डकट और केबल रनवे प्रभार, वितरण ढांचा, स्थानापन्न एसी पावर सहित एसी पावर, डीसी पावर, अन्य भौतिक/पर्यावरणीय सेवाओं सहित वातानुकूलन, सुरक्षा और स्थल अनुरक्षण आदि)		
5. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए रद्दकरण प्रभार (देखें विनियम-12)		
क्र०सं०	प्रति इकाई क्षमता	
(i)	एसटीएम-1	
(ii)	एसटीएम-4	
(iii)	एसटीएम-16	
(iv)	एसटीएम-64	
6. एक्सेस प्राप्तकर्ता होने के नाते पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए कोई अन्य प्रभार अथवा विवरण, जोकि इस प्रपत्र की क्रम संख्या 1 से 5 में निर्दिष्ट नहीं है।		

टिप्पणी: केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के अनुसार केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ-अंतरसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, प्राधिकरण को विचारित लागत-निर्धारण अवयव, उनकी लागत और अपनाई गई लागत-निर्धारण पद्धति तथा अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता एक्सेस और सहस्थान सुविधा के लिए इन विनियमों की अनुसूची के भाग-II में ऊपर दिए गए प्रभार लगाने हेतु तैयार किया गया परिकलन-पत्र उपलब्ध कराएगा।

भाग-III

केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण सेवाओं और सहस्थान सेवाओं के प्रावधान के लिए दी गई समयावधि
(देखें विनियम 4,5,6,7,8,9,15 और 16)

क्रियाकलाप (1)	दिन (समयावधि)
क. एक्सेस सरलीकरण सेवाओं के प्रावधान के लिए समयावधि	
1. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अनुरोध प्रस्तुत करती है।	1 दिन
2. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी व्यवहार्यता की जांच करता है और एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक्सेस सरलीकरण और परीक्षण के लिए स्वीकृति अथवा संशोधित कार्यक्रम भेजता है और उसे बीजक के लिए प्रोफार्मा उपलब्ध कराता है।	11 दिन (अधिकतम 10 दिन)
3. पुष्ट मांग की तारीख {x एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बीजक के अनुसार भुगतान करने सहित एक्सेस सरलीकरण करार पर हस्ताक्षर करने में लिया गया समय है}; नीचे दिए गए खंड (क) के और खंड (ख) के अनुसार x अधिकतम 5 दिनों की समय सीमा है -	11 दिन + x
(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा एक्सेस सरलीकरण करार के लिए समय-सीमा	5 दिन
(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बीजक के अनुसार भुगतान के लिए समय-सीमा	5 दिन

4. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था बैकहॉल की व्यवस्था करती है और उसे उपलब्ध कराती है { y पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बैकहॉल सर्किट की व्यवस्था करने और उसे उपलब्ध कराने में लिया गया समय है}; नीचे दिए गए खंड (क) के अनुसार y अधिकतम 10 दिनों की समय-सीमा है —	10 दिन
(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर बैकहॉल सर्किट क्षमता वाले केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी सहित किसी सेवा प्रदाता से बैकहॉल सर्किट की व्यवस्था करने के लिए समय-सीमा।	10 दिन
5. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को संदर्भ क्षमता के एक्सेस की सुविधा देने के मददेनजर सभी क्रियाकलाप पूरा करने का समय	22 दिन+x+y (अधिकतम 10 दिन)
6. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन को संदर्भ क्षमता प्रदान करता है और पांचवां चरण पूरा होने के बाद अधिक से अधिक 2 दिनों में तत्काल उसे क्रॉस-कनेक्शन उपलब्ध कराता है।	22/24 दिन+x+y (अधिकतम 2 दिन)
7. अन्य कोई ब्यौरे जो दिए जाने अपेक्षित हों किंतु इस प्रपत्र के पैरा क के क्रम संख्या 1 से 6 में निर्दिष्ट न हों।	
ख. सह-स्थान सेवाओं के लिए समय अवधि	
1. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अनुरोध प्रस्तुत करती है।	1 दिन
2. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी व्यवहार्यता की जांच करता है और एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को स्वीकृति अथवा कारणों और वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ अस्वीकृति भेजता है।	11 दिन (अधिकतम 10 दिन)
3. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह-स्थान का प्रावधान उपलब्ध कराता है (Z एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह-स्थान करार पर हस्ताक्षर करने और प्रभारों का भुगतान करने हेतु लिया गया समय है); Z नीचे दिए गए खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार अधिकतम 5 दिनों की समय-सीमा है —	12 दिन + Z
(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह-स्थान द्वारा सह-स्थान करार के लिए समय-सीमा	5 दिन
(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह-स्थान हेतु प्रभारों के भुगतान के लिए समय-सीमा	5 दिन
4. अन्य कोई ब्यौरे जो दिए जाने अपेक्षित हों किंतु इस प्रपत्र के पैरा ख के क्रम संख्या 1 से 3 में निर्दिष्ट न हों।	

भाग-IV**सह-स्थान सुविधा और सेवाओं के लिए अनुरोध का प्रपत्र**
(देखें विनियम-15)

अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह-स्थान सुविधा के अनुरोध के लिए आवेदन-पत्र

मैसर्स (एक्सेस की मांग करने वाले का नाम)

एतद्वारा सह-स्थान सुविधा का अनुरोध करता है, जो केबल लैंडिंग स्टेशन पर अनिवार्य सुविधाओं (समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित) के लिए दूरसंचार एक्सेस विनियमों, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए "केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस-आरआईओ) में प्रकाशित निबंधन और शर्तों के अधीन है।

मैसर्स निम्नानुसार आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें।

1. कंपनी का नाम और उसका पता	
2. बिलिंग पता	
3. संपर्क व्यक्ति	
3.1 नाम:	
3.2 दूरभाष सं०:	
3.3 ई-मेल:	
3.4 फैक्स:	
4. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का ब्यौरा	
4.1 अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर	
4.2 इंटरनेट सेवा प्रदाता	
4.3 लाइसेंस संख्या	
4.4 लाइसेंस जारी करने की तारीख	
5. सह-स्थान के लिए अनुरोध करने वाली पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का ब्यौरा	
5.1 आवेदन की तारीख	
5.2 आवेदन संदर्भ सं०	
5.3 के प्रयोजनार्थ मांगी गई वास्तविक एक्सेस के लिए अनुमोदन	

5.4 संदर्भ तारीख/एक्सेस का समय			
5.5 एक्सेस की अनुमानित अवधि			
5.6 उन व्यक्तियों के नाम जिनके लिए वास्तविक एक्सेस अपेक्षित है	सं.	व्यक्ति का नाम	संपर्क नंबर
	1		
	2		
	3		
	4		
5.7 सह स्थान स्थल जहां पर सह-स्थान जगह देने का अनुरोध किया गया है।			
5.8 समुद्री केबल क्षमता एक्सेस करने का प्रयोजन			
5.9 लगाया जाने वाला प्रस्तावित सह-स्थान उपकरण			
5.10 स्थान और बिजली संबंधी आवश्यकता			
5.11 सह-स्थान उपकरण की फ्लोर लोडिंग			
5.12 अपेक्षित ट्रांसमिशन टाई-केबल की क्षमता			
5.13 प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार			
6. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की ओर से			
6.1 नाम:			
6.2 पदनाम:			
6.3 संपर्क नंबर:			
6.4 फैंक्स नंबर:			
6.5 ई-मेल आइडी:			
6.6 कंपनी की मुहर:			
6.7 हस्ताक्षर			

7. अनुरोध करने वाले पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उत्तर देने वाले केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी (नाम)	
7.1 आवेदन लौटाया गया— अधूरा/अपठनीय	
7.2 स्वीकृत नहीं किया गया	
7.3 अस्वीकृत करने के कारण	
8. संलग्न प्रमाण—पत्र में दिए गए ब्यौरों और शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत	
8.1 वैकल्पिक तारीख और समय	
8.2 वैकल्पिक सह-स्थान जगह (यदि लागू हों)	
8.3 केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी का स्वीकृत कोड	
9. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी की ओर से	
9.1 नाम:	
9.2 पदनाम:	
9.3 संपर्क नंबर:	
9.4 फैक्स नंबर:	
9.5 ई-मेल आईडी:	
9.6 कंपनी की मुहर:	
9.7 हस्ताक्षर	

भाग—V

सह-स्थान उपकरण स्थापना और अनुरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश
(देखें विनियम-19)

1. सह-स्थान जगह पर उपकरण की स्थापना

1.1 सह-स्थान पर उपकरण स्थापित करना

(क) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने सह-स्थान उपकरणों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले विस्तृत स्थापना योजना और स्थापना कार्यक्रम प्रस्तुत करे।

(ख) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह सुनिश्चित करे कि उसके सह-स्थान उपकरण की फ्लोर लोडिंग सीमित हो जैसी कि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट है। एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह प्रमाणित करे कि फ्लोर लैंडिंग सीमा यथाविनिर्दिष्ट से अधिक नहीं होगी।

(ग) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अंतिम स्थल निरीक्षण, अथवा जैसा कि परस्पर सहमति हुई हो, के पश्चात् नब्बे कार्यदिवसों के भीतर सह-स्थान जगह पर अपने सह-स्थान उपकरण स्थापित करे। यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने तर्कसंगत नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण उपकरणों की स्थापना करने में विफल रहती है तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उसके अनुरोध पर स्थापना के लिए एक तर्कसंगत समय विस्तार की अनुमति देगा। इस खंड के अंतर्गत अनुरोध करने वाली पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने नियंत्रक से परे की परिस्थितियों के बारे में बताएगी और ऐसा अनुरोध ऊपरलिखित नब्बे कार्य दिवस की अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

(घ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह-स्थान जगह में सह-स्थान उपकरण से अलग उपकरण स्थापित न करे।

1.2 ऑप्टिकल फाइबर केबल

जब तक कि पक्षकर अन्यथा सहमत न हों, एक्सेस की मांग कर रही भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह-स्थान जगह पर और सह-स्थान जगह से बाहर लीड इन मेनहॉल तक दो से अधिक वास्तविक ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापित न करें

1.3 पावर और अर्थ

यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था चाहे तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए एक्सचेंज अर्थ और पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट नामित करेगा और उपलब्ध कराएगा। एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को एक्सचेंज अर्थ और पावर स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था करने के लिए सह-स्थान मूल्य सूची में प्रकाशित प्रभारों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगी।

1.4 हस्तक्षेप

प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करे कि सह-स्थान पर उसके सह-स्थान उपकरण दूसरे पक्षकारों के उपकरण, संयंत्र, सुविधाओं, नेटवर्क तथा एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपकरण में कोई बाधा उत्पन्न न करे और इसका उपकरण स्थापना के समय भी ध्यान रखा जाए। किसी हस्तक्षेप की स्थिति में पक्षकार समस्या को तत्काल सुलझाने के लिए एक दूसरे को विश्वास में लेकर तर्कसंगत उपाय करेंगे। जहां पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपकरण विद्यमान उपकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और हस्तक्षेप का समाधान नहीं हो सकता है, वहां पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था तुरन्त अपने हस्तक्षेप स्रोत को हटाए।

1.5 मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और सुरक्षा

(क) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह-स्थान जगह में स्थापित अपने सह-स्थान उपकरण की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में सह-स्थान जगह के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और किसी अन्य लिखित अनुदेशों, जो केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उपलब्ध कराए गए हैं, का पालन करेगा।

(ख) सह-स्थान जगह की वास्तविक एक्सेस के संबंध में पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था समय-समय पर यथासंशोधित केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी हेतु मानक वास्तविक एक्सेस प्रक्रियाओं का और किसी अन्य लिखित अनुदेशों, जो केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उपलब्ध कराए गए हैं, का पालन करेगा।

(ग) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, सह-स्थान जगह जिनके लिए उपकरण की स्थापना, संशोधन, प्रतिस्थापन अथवा यह जांच करने के लिए उपकरणों में वृद्धि करने के लिए एक्सेस का अनुमोदन किया गया है कि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था योजना और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उपलब्ध अन्य लिखित अनुदेशों के अनुरूप उपकरण की स्थापना, संशोधन, अनुरक्षण, प्रचालन, प्रतिस्थापन या उपकरणों में वृद्धि की गई है, का निरीक्षण इसके प्रतिनिधियों/स्टाफ द्वारा कराएगा।

(घ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था फर्श, दीवार और सीलिंग स्लैबों पर कोई हैकिंग या ड्रिलिंग काम करने से पहले केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से सलाह करेगा और उसकी सहमति प्राप्त करेगी।

(ङ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था किसी भी उपकरण, सुविधाओं, संयंत्र अथवा नेटवर्क पर कोई काम नहीं करेगा किंतु केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के अर्थ बार और पावर डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंटों/बोर्डों पर काम करने की कोई पाबंदी नहीं है।

(च) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी का स्टाफ, एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सभी अंतरसंयोजनों को केबल लैंडिंग अर्थ बार और पावर डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंटों/बोर्डों के स्वामी के सह-स्थान उपकरण से जोड़ेगा। इस काम का खर्च पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वहन करेगी जैसा कि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा प्रकाशित सह-स्थान प्रभारों में दिया गया है।

(छ) जहां पर, एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने सह-स्थान उपकरणों की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रतिस्थापन या मरम्मत के दौरान केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के सह-स्थान जगह, संयंत्र, नेटवर्क, उपकरण अथवा सुविधाओं को कोई नुकसान पहुंचाती है, तो एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को तत्काल नुकसान के बारे में बताएगी। केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उस नुकसान को किसी भी प्रकार से, जिसे वह उचित समझे, ठीक कराएगा और उसकी लागत और खर्च एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वहन करेगी।

1.6 अंतिम निरीक्षण

(क) सह-स्थान जगह पर सह-स्थान उपकरण की स्थापना का काम पूरा होने पर एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से अंतिम निरीक्षण करने और इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध करेगी कि स्थापना अनुमोदित विस्तृत स्थापना योजना के अनुसार की गई है।

(ख) जहां पर अंतिम निरीक्षण से यह पता चले कि स्थापना अनुमोदित विस्तृत स्थापना योजना के अनुसार नहीं की गई है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को इसके बारे में अधिसूचित करेगा। एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अधिसूचना के दस (10) कार्य दिवसों अथवा ऐसे किसी समय, जिस पर सहमति हुई हो, के भीतर पुनर्स्थापना करेगी अथवा अन्य उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करेगी।

(ग) यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था पुनर्स्थापना अथवा खंड 1.6 (ख) में दी गई उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सह-स्थान उपकरणों को हटाने सहित उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करेगा। सुधारात्मक कार्यवाही की उचित लागत का वहन एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था करेगी।

2. सह-स्थान जगह पर सह-स्थान उपकरण का अनुरक्षण

2.1 एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने सह-स्थान उपकरणों के प्रचालन और अनुरक्षण अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ जैसी सहमति हुई हो, के लिए जिम्मेदार होगी।

2.2 यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सह-स्थान उपकरण में कोई त्रुटि, खराबी अथवा समस्या, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के सह-स्थान जगह अथवा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाती है तो एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था:

- (क) जितनी जल्दी हो व्यावहारिक हो, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अधिसूचित करेगी; और
- (ख) त्रुटि, खराबी अथवा समस्या को तत्काल ठीक करेगी या अन्य उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करे।

2.3 एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा ही इस अनुसूची के अंतर्गत केबल लैंडिंग स्टेशन पर निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल पर एक्सेस संदर्भ क्षमता के साथ पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था नेटवर्क को जोड़ने के प्रयोजन के लिए अथवा बैकहॉल सर्किट का प्रावधान करने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर स्थित सेवा प्रदाताओं के उपकरण/नेटवर्क के साथ अंतरसंयोजन के लिए सह-स्थान उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

2.4 अनुपालन

(क) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी, एजेंट और अनुमोदित उप-संविदाकार समय-समय पर अधिसूचित केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के निर्देशों और सभी उपयुक्त प्रक्रियाओं सहित इस दस्तावेज के उपबंधों का अनुपालन करेगी।

(ख) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था काम करते समय सभी कानूनों, मानकों, प्रमाणनों और पट्टों का पालन करेगी।

(ग) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उसे काम करने अथवा सेवा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति, सरकारी विनियामक अथवा संगत प्राधिकरण से सभी आवश्यक परमिट अनुमोदन और पट्टे प्राप्त हैं।

(घ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का सह-स्थान जगह पर कोई अधिकार, हक अथवा स्वामित्व हित नहीं होगा।

2.5 उपकरण का चिन्हन

एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह-स्थान उपकरणों को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा दिए गए निदेशानुसार इस तरीके से चिन्हित करेगी कि यह स्पष्ट हो सके कि इसे पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा पट्टे पर लिया गया है।

भाग-VI

सह-स्थान जगह के वास्तविक एक्सेस हेतु प्रमाणन पत्र का प्रपत्र (देखें विनियम 20)

यह प्रमाणन-पत्र दिनांक के संदर्भ के माध्यम से अनुरोध आवेदन को दी गई अंतिम स्वीकृति के संयोजन में जारी किया गया है।

इसे नीचे यथाइंगित सह-स्थान जगह हेतु दी गई एक्सेस की अवधि के दौरान पूरे समय तारीख अभिहित पर्यवेक्षक/व्यक्ति द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

एक्सेस के लिए सह-स्थान जगह की स्थिति -

[स्थिति/भवन का नाम]

फोटो पहचान

1. एक्सेस की अनुमोदित तारीख
2. एक्सेस का अनुमोदित समय
3. एक्सेस की अनुमोदित अवधि

केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी की ओर से

हस्ताक्षर

संपर्क दूरभाष नंबर

फैक्स नंबर

भाग—VII

प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और ब्यौरे
(देखें विनियम-20)

क्र०सं०	पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था (एक्सेस प्राप्तकर्ता) के व्यक्ति/प्रतिनिधि/ठेकेदार का नाम	पहचान पत्र सं०	संपर्क दूरभाष नंबर	फैक्स नंबर
1				
2				
3				
4				
—				

आर. के. आर्नल्ड, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./142/07]

टिप्पणी : यह व्याख्यात्मक ज्ञापन केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5) के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पृष्ठभूमि

1.1 अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) इंटरनेट, ब्रॉडबैंड तथा आईपी समर्थकारी सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण अवयव है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में दूरवर्ती छोर आईपीएलसी, अर्ध सर्किट, निकटवर्ती छोर आईपीएलसी अर्ध सर्किट तथा समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशनों तक एक्सेस शामिल होती है। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी दूरसंचार सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलते समय, सरकार ने महसूस किया था कि समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन अनिवार्य रूप से एक बाधक सुविधा है तथा यह तथ्य भी ध्यान में रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी एक्सेस इंकम्बेंट अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) प्रचालक की अधिपत्यात्मक स्थिति द्वारा अनेक प्रकार से प्रभावित होगी।

1.2 अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी खंड में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (द्राई) ने जून 2005 में एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की थी। द्राई ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किटों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के उपायों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 16 दिसम्बर, 2005 को सिफारिशें की थीं। अनिवार्य सुविधाओं, जिनमें समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं, की एक्सेस से संबंधित द्राई की सिफारिशें लाइसेंसर द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। लाइसेंसर ने आईएलडी लाइसेंस में प्रासंगिक खंडों को संशोधित भी किया है ताकि द्राई केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों के लिए अनिवार्य सुविधाओं (जिनमें लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं) की दक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्वक एक्सेस सुनिश्चित करने हेतु विनियम बनाने के लिए समर्थ हो सके।

1.3 अतः द्राई ने केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित अनिवार्य सुविधाओं हेतु दक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए विनियम निकालने के प्रयोजन के लिए एक परामर्श-पत्र जारी किया जिसमें मसौदा विनियम भी शामिल था तथा जिसमें केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) तथा सीएलएस पर उपस्कर के सह-स्थान पर समुद्री केबलों के लिए एक्सेस की सुविधा हेतु प्रस्तावित विभिन्न निबंधन एवं शर्तों का विस्तृत विवरण भी दिया गया था। पणधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मसौदा विनियम के साथ परामर्श-पत्र 13 अप्रैल, 2007 को जारी किया गया। पणधारियों को लिखित टिप्पणियां 30 अप्रैल, 2007 तक प्रस्तुत करनी थीं। कुछ पणधारियों के अनुरोध पर लिखित टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए तारीख को बढ़ाकर 7 मई, 2007 तक कर दिया गया। एटी एंड टी, औरेंज बिजनेस सर्विसेज, बीटी ग्लोबल सर्विसेज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारती, वीएसएनएल, रिलायंस, केबल्स एवं वायसलैस, सिफी कम्युनिकेशंस लि., वेरीजन कम्युनिकेशंस प्रा. लि., आईएसपीआई, टेलसेक्स कंसल्टिंग सर्विस प्रा. लि. तथा एशिया पैसेफिक कैरियर्स कोएलीशन से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। टिप्पणियां प्रस्तुत करने की विस्तारित तारीख अर्थात् 7 मई 2007 तक पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों के सार को द्राई की वेबसाइट पर रखा गया था। पणधारियों के साथ दिल्ली में 14 मई, 2007 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई जिसमें पणधारियों ने विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

2. पणधारियों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों तथा उठाए गए मुख्य मुद्दों की जांच

2.1 प्राधिकरण ने पणधारियों की विभिन्न टिप्पणियों तथा सुझावों पर विचार किया तथा मामले का विस्तार से विश्लेषण किया। स्पष्टता की दृष्टि से पणधारियों द्वारा की गई टिप्पणियों तथा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है तथा उसके पश्चात् मुद्दे पर प्राधिकरण का विचार तथा निर्णय दिया गया है।

2.2 मुद्दा 1 – विनियम की प्रयोज्यता और आवश्यकता

2.2.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश नीचे पैरा (क) से (घ) में दिया गया है तथा उनके पश्चात् आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है।

(क) केवल प्रधान प्रचालकों द्वारा नियंत्रित केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस, सह-स्थान तथा बैंकहॉल व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रस्तावित विनियम की व्याप्ति को कम किया जाना चाहिए।

(ख) केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं और सह-स्थान की एक्सेस के लिए सीएलएस – आरआईओ को संबंधित लैंडिंग स्टेशन प्रचालक द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा किसी भी पूर्व विनियम को बहाल नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) सीएलएस के लिए एक्सेस सुविधा विनियम की अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं और साथ ही सीएलएस पर सह-स्थान सुविधाओं की एक्सेस को सरल बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

(घ) इस विनियम का विस्तार नई समुद्री केबलों हेतु लैंडिंग व्यवस्थाओं को अधिदेशित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

2.2.2 इस मामले में, प्राधिकरण ने नोट किया कि अधिकांश पणधारी समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए एक्सेस और सह-स्थान अधिदेशित किए जाने के पक्ष में हैं, जोकि अनेक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं के लिए एक अनिवार्य निवेश है। प्राधिकरण ने आगे यह भी नोट किया कि केवल प्रधान / इंकम्बेंट प्रचालकों द्वारा नियंत्रित केबल लैंडिंग स्टेशन पर एक्सेस, सह – स्थान तथा बैंकहॉल व्यवस्था को अधिदेशित करने की इस विनियम की व्याप्ति को सीमित करने से बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होंगे तथा यह स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अभ्युदय को भी बाधित करेगा। यह एक्सेस के लिए अनुरोध को पूरा करने के लिए केवल प्रधान / इंकम्बेंट प्रचालकों पर बोझ और बाध्यता भी डालेगा तथा इस कारण यह उचित नहीं है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ एक्सेसिंग में वर्तमान में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भी विद्यमान नहीं है। अतः क्षेत्र में प्रभावी प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए सभी केबल लैंडिंग स्टेशनों, जिनमें भविष्य में चालू होने वाले स्टेशन भी शामिल हैं, के स्वामियों के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस – आरआईओ) को अधिदेशित करने की आवश्यकता है।

2.3 मुद्दा 2 — नए केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों द्वारा प्राधिकरण को मसौदा सीएलएस-आरआईओ के प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा

2.3.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं

संगत सीएलएस स्वामियों को चाहिए कि नई केबल सिस्टम को सक्रिय करने से पहले छह महीने से अन्यून अवधि का मसौदा आरआईओ उपलब्ध कराएं।

2.3.2 स्वामी द्वारा नई केबल लैंडिंग स्टेशन आरंभ करने से छह महीने पूर्व प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए मसौदा सीएलएस-आरआईओ को प्रस्तुत किया जाना कुछ मामलों में संभव नहीं होगा। उद्योग के साथ चर्चा में यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि भारत में अन्तरराष्ट्रीय केबल प्रणाली की स्थापना करना लंबा समय लेने वाली जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की निकासियों जैसे सुरक्षा निकासी, सामुद्रिक निकासी और सिविल प्राधिकरण की अनुमति आदि शामिल हैं। अतः केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन को आरंभ किए जाने की सही तारीख का विनिश्चयन कर पाना संभव नहीं है। अतः प्राधिकरण की राय है कि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा प्राधिकरण को केबल लैंडिंग स्टेशन आरंभ करने की तारीख को या उससे पूर्व अपना सीएलएस-आरआईओ प्रस्तुत किया जाना ही पर्याप्त है।

2.4 मुद्दा 3 — केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी (ओसीएलएस) द्वारा प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए सीएलएस-आरआईओ पर अन्य पक्षकारों की टिप्पणी

2.4.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त हुई —

अन्य पक्षकार अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावित सीएलएस-आरआईओ अवधि पर टिप्पणी देना चाहेंगे।

2.4.2 प्राधिकरण ने एक पणधारी के इस दृष्टिकोण को नोट किया और उसकी यह राय है कि ओसीएलएस द्वारा अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत सीएलएस-आरआईओ पर टिप्पणियां मंगाना संगत और उपयुक्त नहीं होगा। चूंकि ओसीएलएस को सीएलएस-आरआईओ प्रस्तुत करते समय सीएलएस-आरआईओ के विभिन्न भागों में निर्धारित प्रभारों को निकालने के लिए अपनाई गई नेटवर्क लागत घटक और लागत निकालने के लिए अपनाई पद्धति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया है। अतः प्राधिकरण की राय है कि पणधारियों से पुनः टिप्पणियां मंगाना परामर्श की पुनरावृत्ति होगी जिससे पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होगा।

2.5 मुद्दा 4 — उन्नयन के लिए समय-सीमा

2.5.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया गया है और उसके बाद उन पर विचार किया गया है।

(क) किसी भी प्रकार की उन्नत सुविधा का लाभ विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार होना चाहिए।

(ख) गैर-उपलब्धता की दशा में को-लोकेशन स्पेस के उन्नयन के लिए ओसीएलएस को अधिदेश देने के लिए विनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

2.5.2 समुद्री केबल क्षमता पर पहुंच हेतु क्षमता उन्नयन के लिए अनुरोध करने वाले आईटीई द्वारा उपस्करों की खरीद की जानी अपेक्षित है चूंकि ऐसे अपेक्षित उन्नयन की पूरी लागत का वहन अनुरोध करने वाले आईटीई या विदेशी समुद्री केबल क्षमता के स्वामी जिसके साथ आईटीई ने रेफरेंस क्षमता के अधिग्रहण के लिए करार किया गया है, द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नई लैंडिंग अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन्नयन के मूल घटक मामले के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। अतः ओसीएलएस को उनके प्रभार निर्धारण और समय-सीमा के लिए और पारदर्शी होने के लिए आदेशित किया जाना ही पर्याप्त होगा और इसे वैश्विक प्रथाओं के अनुसार आपसी बातचीत पर छोड़ देना ही सर्वोत्तम होगा।

2.6 मुद्दा 5 – एक्सेस सुविधा समापन से पूर्व सूचना

2.6.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं –

सीएलएस स्वामी द्वारा सेवा का समापन करने से पूर्व 30 दिनों की भुगतान अवधि के अतिरिक्त सीएलएस स्वामी द्वारा आईटीई को 14 दिनों को पूर्वलिखित सूचना (दोष सुधार के अवसर के साथ) देनी अपेक्षित होगी।

2.6.2 प्राधिकरण ने समापन से पूर्व सूचना के बारे में पणधारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि यदि अर्हक भारतीय दूरसंचार संस्था द्वारा शोध्य और देय वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार, ऐसे प्रभार देय होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक अदेय रहते हैं तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र आईटीई को ऐसे समापन की 15 दिनों से अन्यून की अवधि में एक लिखित नोटिस देकर उसे उपलब्ध एक्सेस सुविधा को समाप्त कर सकता है। प्राधिकरण की यह राय भी है कि समापन से पहले की नोटिस की अवधि को लेने से विवादों से भी बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नोटिस अवधि से एक और लाभ यह होगा कि प्रभावित पक्ष अर्थात् अर्हक भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था दोष का सुधार कर सकेगी तथा अंतिम उपभोक्ता भी प्रभावित नहीं होंगे।

2.7 मुद्दा 6 – बैंकहॉल सर्किट के प्रावधान के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर बैंक हॉल सुविधा का अंतरसंयोजन और लीजिंग अधिदेश

2.7.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया जा रहा है और उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) विनियमों से केबल लैंडिंग स्टेशन पर दो को-लोकेटिंग आईटीई के बीच अंतरसंयोजन होना चाहिए। यह आईटीई के बीच अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक हैण्डऑफ के लिए क्षमता प्रदान करेगा और उन्हें सुविधा के भीतर कई बैंकहॉल सेवा प्रदाताओं के साथ एक्सेस प्रदान करेगा।

(ख) प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन पर प्रतिस्पर्धी बैंकहॉल सेवाओं को विकसित करने से पूर्व इन सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी आईएलडीओ द्वारा अनुचित प्रभार का भुगतान न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए लागत अभिमुख दरों पर अंतरिम अवधि के लिए प्रधान केबल स्टेशन प्रचालकों द्वारा बैंकहॉल सुविधा को लीज पर देने के लिए ट्राई द्वारा अधिदेश दिया जाना चाहिए।

2.7.2 केबल लैंडिंग स्टेशन के प्रधान स्वामी को बैकहॉल सुविधा को लीज पर देने के लिए अधिदेश दिए जाने से अतिरिक्त बैकहॉल सुविधा का सृजन हतोत्साहित होगा। केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को बैकहॉल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश देने की बजाय यह बेहतर होगा कि किसी भी सेवा प्रदाता से बैकहॉल सुविधा लेने में लोचता प्रदान करने के लिए अधिदेश देने से बैकहॉल सुविधा के लिए अर्हक आईटीई को और अधिक लाभ और विकल्प उपलब्ध होंगे। इस विनियम में प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य उपलब्ध अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए एक्सेस का प्रावधान अधिदेशित करना है और बैकहॉल सर्किट का प्रावधान उपयुक्त शर्त और लोचता पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2.7.3 सीएलएस पर को-लोकेटिंग आईटीई/बैकहॉल सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन से बैकहॉल सर्किट का तीव्र प्रावधान प्रतिस्पर्धी दर पर हो सकेगा। अर्हक आईटीई भी वहां उपस्थित अन्य सेवा प्रदाताओं की बैकहॉल सर्किट क्षमता का उपयोग करके सीएलएस पर अपने उपस्कर को स्थापित किए बिना भी अन्तरराष्ट्रीय रेफरेस क्षमता के एक्सेस के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे केबल लैंडिंग स्टेशन को-लोकेशन के लिए अनुरोध पर दबाव भी कम हो सकेगा। इसका दूसरा लाभ यह होगा कि बैकहॉल सर्किट के प्रावधान के लिए ओसीएलएस को अधिदेशित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा अर्हक आईटीई के पास केबल लैंडिंग स्टेशन पर बैकहॉल सर्किट क्षमता रखने वाले ओसीएलएस सहित किसी भी बैकहॉल सर्किट सेवा प्रदाता से प्रतिस्पर्धी दर पर बैकहॉल सर्किट लेने का विकल्प होगा। अतः प्राधिकरण ने इन विनियमों में तदनुसार उपयुक्त प्रावधान किए हैं।

2.8 मुद्दा 7 – एक्सेस सुविधा के लिए प्रभार तथा प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रभार क्षमता से बंधे नहीं होंगे

2.8.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया गया है और उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) क्रास कनेक्शन सेवाओं के लिए प्रभार क्षमता से बंधे नहीं होंगे। सीएलएस पर वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध वार्षिक आवर्ती एक्सेस प्रभार केबल क्षमता के प्रति एसटीएम-1 या 155 एमबीपीएस के आधार पर लगाया जाता है। इसमें क्षमता और सेवा प्रावधान की लागत के बीच कोई गठजोड़ नहीं है।

(ख) प्रभार लागत अभिमुख होने चाहिए, एक्सेस सुविधा प्रभार, वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार और पुनःबहाली प्रभार "प्रति यूनिट क्षमता" के आधार पर नहीं होने चाहिए। लागत अभिमुख फीस संरचना में प्रति यूनिट क्षमता आधार पर आने वाली एक्सेस लागत को ही उस आधार पर प्रभारित किया जाना चाहिए।

2.8.2 प्राधिकरण ने पणधारियों की इस राय को नोट किया और वह सीएलएस के स्वामियों द्वारा नेटवर्क घटकों की लागत, लागत निर्धारण पद्धति और परिकलन शीट आदि विवरणों के साथ अनुमोदन के लिए अपना सीएलएस-आरआईओ प्रस्तुत करने के बाद इस विषय की जांच करेगा और उस पर विचार करेगा। इस अवस्था में प्राधिकरण ने ओसीएलएस द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन

के पश्चात् प्रकाशित किए जाने वाले प्रभारों के प्रकटन के लिए इन विनियमों में संलग्न अनुसूची के माध्यम से आधारभूत फ्रेमवर्क प्रदान किया है।

2.9 मुद्दा 8 — सुरक्षा मॉनिटरिंग सुविधा की साझेदारी

2.9.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया गया है और उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) नए आईएलडी प्रचालकों के साथ सीएलएस पर सुरक्षा मॉनिटरिंग सुविधाओं की साझेदारी को अधिदेशित किया जाना चाहिए।

(ख) नए आईएलडी लाइसेंस की शर्तों में लेयर 2 और लेयर 3 वीपीएन सेवाओं को प्रदान करने के लिए विद्यमान लाइसेंसी जिससे अन्तरराष्ट्रीय संयोजन के लिए आपसी करार किया गया है के साथ मॉनीटरिंग क्षमताओं की साझेदारी का प्रावधान है, इस लाइसेंस में दिए गए प्रावधान नए आईएलडी प्रचालक को अल्प समय अवधि में अपनी सुरक्षा मॉनीटरिंग उपस्कर की स्थापना के लिए प्रतीक्षा किए बिना सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाता है जिससे नए प्रचालकों के लिए संभावित अवरोधों में कमी लाई जा सकती है।

(ग) अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाएं जो केबल-लैंडिंग स्टेशन से क्षमता को एक्सेस कर रही हैं उनके पास अपनी डेटा और वॉयस मॉनीटरिंग प्रणाली होनी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाएं निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार सभी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए।

2.9.2 अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक (आईएलडीओ) लाइसेंस की दशाओं के माध्यम से उन पर लगाए गए सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। लाइसेंसरों ने पहले ही आईएलडी, जिसमें आईएलडीओ के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग उपस्कर स्थापित करना आवश्यक है, के माध्यम से आईएलडीओ के लिए सुरक्षा शर्तों के लिए पहले ही अधिदेशित किया है। केबल लैंडिंग स्टेशन में अनिवार्य एक्सेस किसी सुरक्षा शर्त, जो संबंधित लाइसेंसी के अनुसार अपेक्षित है, को किसी भी तरह कम नहीं करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, अर्हक आईटीई/नए आईएलडीओ के साथ सीएलएस पर सुरक्षा मॉनीटरिंग सुविधा की भागीदारी संबंधित लाइसेंसों और उनमें इस संबंध में निर्दिष्ट की गई शर्तों से शासित होंगी। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि इन विनियमों में इस मुद्दे के लिए किसी प्रकार के विनियम या अधिदेश के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

2.10 मुद्दा 9 — ट्राई द्वारा अंतरसंयोजन करार का पूर्वानुमोदन

2.10.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं

सिद्धांत रूप में सीएलएस-आरआईओ में अनुसरण में केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों और अर्हक आईटी के बीच सभी करार ट्राई द्वारा पूर्वानुमोदित होने चाहिए। इस संबंध में एक्सेस सुविधा करार पूर्वानुमोदित सीएलएस-आरआईओ का एक भाग होना चाहिए। इस से किसी

संभावित विलंब से बचा जा सकेगा और कोई भी मनमुटाव पर वाणिज्यिक दृष्टि से बातचीत की जा सकेगी और केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस का समय पर बेहतर प्रावधान करने तथा आवश्यक सुविधाओं के कोलोकेशन से किया जा सकेगा।

2.10.2 प्राधिकरण की यह राय है कि एक बार ट्राई द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन रेफरेंस अंतरसंयोजन ऑफर (सीएलएस-आइआईओ) का अनुमोदन करने तथा ओसीएलएस द्वारा उस आधार जिस पर ऐसा एक्सेस सुविधा करार किया गया है, को प्रकाशित करने के पश्चात अनुमोदनकर्ता की भूमिका का निर्वहन नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और पक्षपातहीनता बनाए रखने के लिए यह उपयुक्त होगा कि प्राधिकरण को करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए अंतरसंयोजन करार प्रस्तुत कर दिया जाए। तदनुसार इन विनियमों में उपबंध किए गए हैं।

2.11 मुद्दा 10 आईएसपी के लिए अंतरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति

2.11.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं —

अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति रखने वाले आईएसपी के रूप में अर्हक आईटीई में दोनों प्रकार की अर्थात् समुद्री केबल गेटवे और/या सेटैलाइट गेटवे अनुमति शामिल की जानी चाहिए।

2.11.2 इस संबंध में यह समझा गया कि समुद्री केबल क्षमता पर केबल लैंडिंग स्टेशनों के माध्यम से और सेटैलाइट मीडिया पर सेटैलाइट अर्थ स्टेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अन्तरराष्ट्रीय लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) के माध्यम से इंटरनेट बैंडविथ को पूरा करने के लिए पृथक अन्तरराष्ट्रीय आईएसपी गेटवे की अनुमति नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय गेटवे युक्त आईएसपी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उस पर लगाए गए सुरक्षा शर्तों के माध्यम से उन पर लगाए गए सुरक्षा शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। लाइसेंस प्रदान ने इस बारे में अपने लाइसेंस के माध्यम से आईएसपी के लिए सुरक्षा संबंधी शर्तें पहले ही अधिदेशित की हैं जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग उपस्कर स्थापित करना तथा सुरक्षा एजेंसियों से क्लियरेंस के पश्चात आईएसपी अन्तरराष्ट्रीय गेटवे के प्रचालन के लिए दूरसंचार विभाग से इसके लिए आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करना शामिल है। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि यदि किसी आईएसपी के पास अनुमति तथा सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा मॉनीटरिंग सुविधाएं हैं तो यह अर्हक आईटीई होने के नाते केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अन्तरराष्ट्रीय रेफरेंस क्षमता के लिए सुविधा की मांग कर सकता है।

2.12 मुद्दा 11 — एक्सेस का अनुमोदन और को-लोकेशन प्रभार

2.12.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियां नीचे पैरा (क) से (ग) में संक्षेप में दी गई हैं और उन पर उसके बाद में निम्नलिखित पैराग्राफों में विचार किया गया है —

(क) को-लोकेशन और एक्सेस के लिए प्रभारों का निर्धारण प्रथमतः केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी द्वारा संगत लागत के आधार पर की जानी चाहिए तथा उसे निहित लागत घटकों संबंधी सूचना के साथ ट्राई को प्रस्तुत करना चाहिए। ट्राई को इन प्रभारों का मूल्यांकन

अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्किंग दृष्टिकोण से अन्य देशों में प्रचलित उसी प्रकार के प्रभारों के साथ तुलना करके करनी चाहिए।

(ख) रियल एस्टेट, बिजली, मानव संसाधन, एयरकंडीशनिंग, कर आदि की लागत और सीएलएस से एक सुविधाजनक स्थान पर एक्सेस के प्रावधान के लिए क्षमता के विस्तार की लागत अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। यदि ओसीएलएस को अपने प्रभारों में गैर पक्षपातपूर्ण और पारदर्शी होने के लिए अधिदेशित किया जाता है तो वही पर्याप्त होगा।

2.12.2 प्राधिकरण ने इस सिद्धांत की जांच की कि क्या एक्सेस सरलीकरण और सह स्थान प्रभारों के लिए लागत आधारित प्रभारों को विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने की जरूरत है अथवा एक्सेस सरलीकरण और सह स्थान आदि के लिए ओसीएलएस को गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी प्रभारों के रूप में प्रकाशित किए जाना आदेशित है। प्राधिकरण ने यह देखा कि अधिकांश देशों में ओसीएलएस विनियामक की पूर्व अनुमति से प्रभारों को प्रकाशित करता है। प्राधिकरण का यह भी मत है कि तर्कसंगत और वाजिब प्रभारों के लिए यह जरूरी है कि ऐसे प्रभार वास्तविक लागत पर आधारित हों और यह केवल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को पहला मौका भी प्रदान करें। यह सही है कि ओसीएलएस एक्सेस सरलीकरण, प्रचालन और अनुरक्षण, रद्दकरण और सह स्थान स्थल सहित सह स्थान सुविधाओं की व्यवस्था करने और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने में अंतर्ग्रस्त लागत को ध्यान में रखते हुए लागत-मुखी सिद्धांतों के आधार पर प्रभारों का निर्धारण करता है। तथापि, ट्राई, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न विनियमों में प्रयुक्त लागत निर्धारण पद्धति के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर इन प्रभारों को स्वीकृति देगा। ट्राई की पूर्व-अनुमति पारदर्शिता, निष्पक्षता और तार्किकता सुनिश्चित करेगी और ओसीएलएस भी विभिन्न प्रभारों को विनिर्दिष्ट करने में कोई मनमाना दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए, प्राधिकरण ने तदनुसार इन विनियमों में ओसीएलएस को आदेशित किया है।

2.13 मुद्दा 12 – प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने का प्रावधान

2.13.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) से (घ) में दिया गया है और तत्पश्चात् निम्नलिखित पैराओं में उन पर विचार किया गया है –

(क) यदि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी इन विनियमों से इतर किन्हीं अन्य तरीकों सहित किसी भी प्रकार से केबल स्टेशन एक्सेस में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में ट्राई को आईटीई और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रचालकों को भी प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने की अनुमति देनी चाहिए।

(ख) इस फ्रेमवर्क के लागू होने पर, यदि यह असफल हो जाता है तो कोई भी विवादित पक्षकार ट्राई को हस्तक्षेप करने और विवाद का समाधान निकालने के लिए कह सकता है।

(ग) विवाद के मामले में, मामला टीडीएसएटी के क्षेत्राधिकार में होगा।

(घ) ट्राई के सरलीकरण प्रयासों का सदैव स्वागत है।

2.13.2 टीडीएसएटी के पास विवाद समाधान तंत्र है। तथापि, एक केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी और एक पात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बीच करार न होने के मामले में, दोनों, संयुक्त रूप से अधिनियम की धारा 14 क के उपबंधों के पूर्वाग्रह के बिना किसी भी समय प्राधिकरण से करार की प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। इन विनियमों अथवा बनाए गए किसी अन्य विनियम को प्रभावी रूप से प्रवृत्त करने और लागू करने के लिए प्राधिकरण, ट्राई अधिनियम के उपबंध के अनुसार किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि ऐसी शिकायतों के लिए इन विनियमों में कोई अलग प्रावधान करने की कोई जरूरत नहीं है। तथापि, यदि पक्षकार चाहें तो करार करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

2.14 मुद्दा 13 – दण्ड

2.14.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) से (घ) तक दिया गया है और सत्पश्चात् निम्नलिखित पैराओं में उन पर विचार किया गया है –

(क) आदेशित समयावधि का पालन करने में विफल रहने पर दण्ड लगाए जाने को शामिल किए जाने की जरूरत है।

(ख) यदि किसी भी अवस्था में विलम्ब हेतु दण्ड का कोई प्रावधान नहीं होगा तो आदेश अक्षरशः व्यवहार में नहीं लाया जाएगा। कृपया प्राधिकरण सिद्ध विलम्ब के मामले में उपयुक्त और कड़े वित्तीय दण्डों को शामिल करें।

(ग) जब तक किसी उल्लंघन के मामले में कड़े दण्ड की सिफारिश नहीं की जाती है तब तक प्रस्तावित विनियम के उपबंध सच्चे अर्थों में प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि प्राधिकरण उन सभी मामलों में, जहां पक्षकार ने इस विनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है, उपयुक्त विनियमों के माध्यम से ओसीएलएस और पात्र आईटीई, दोनों पर दण्ड लगाए।

(घ) अनावश्यक अथवा अनावश्यक, जटिल प्रक्रियाओं को थोपना, जो एक अनुरोध करने वाले पक्षकार द्वारा अनुपालन न करने के जोखिम को बढ़ाता है (जिससे आवेदक पर दण्ड लगता है अथवा उसका आवेदन रद्द हो जाता है)।

2.14.2 ट्राई अधिनियम के अनुसार

“ प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

29. यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जा सकती है और उस पर एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और दूसरा या परवर्ती अपराध होने पर दो लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और लगातार उल्लंघन करने के मामले में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा जो प्रतिदिन जिसमें अपराध जारी रहा, दो लाख रुपए तक हो सकता है। ”

2.14.3 सेवा प्रदाताओं द्वारा आदेशित समयवधि का पालन न करना ट्राई के विनियम का उल्लंघन है और उस पर ट्राई अधिनियम में उपलब्ध उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि इस संबंध में इन विनियमों में विशेष उपबंध करने की कोई जरूरत नहीं है।

2.15 मुद्दा 14 – भारत में प्राइवेट केबल लैंडिंग के लिए क्षमता के एक्सेस के लिए आदेश देना

2.15.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त हुई है –

प्रस्तावित विनियम भारत में प्राइवेट केबल लैंडिंग के मामले में प्रभावी नहीं होगी। प्रस्तावित विनियम को सही अर्थों में प्रभावी बनाने के लिए, एकीकृत केबल स्वामी अनिवार्य विनियम के प्रति, तकनीकी व्यवहार्यता और क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन, उत्तरदायी होगा।

2.16.2 प्रस्तावित विनियम का क्षेत्र निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी तरीके से केबल लैंडिंग स्टेशन के एक्सेस को आदेशित करना है। ट्राई के लिए एक्सेस सरलीकरण हेतु संदर्भ क्षमता वाले एकीकृत केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामियों के लिए इन विनियमों में कोई ऐसा पृथक प्रावधान करने का कोई औचित्य नहीं है। सभी ओसीएलएस इन विनियमों की एकरूपता के अध्यधीन हैं। तथापि, यदि बाद में जरूरी हुआ और ऐसे एकीकृत केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी, एक्सेस सरलीकरण / सह स्थान सुविधाओं की व्यवस्था के लिए गैर – भेदभावपूर्ण और गलत काम में लगे पाए गए तो ट्राई इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धांतों की आवश्यकता अथवा स्थितिनुसार उपयुक्त विनियामक हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा।

2.16 मुद्दा 15 – सीएलएस – आरआईओ प्रस्तुत करते समय ट्राई को लागत – निर्धारण अवयव और लागत पद्धति उपलब्ध करायी जाए

2.16.1 इस मुद्दे पर पणधारियों की टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) से (ग) में दिया गया है और तत्पश्चात् निम्नलिखित पैराओं में इन पर विचार किया गया है

(क) प्रमुख केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी ट्राई को अनुमोदन हेतु एक्सेस सरलीकरण और सह स्थान के लिए प्रस्तावित प्रभारों को प्रस्तुत करें तथा लागत संघटकों के बारे में अपनी चिंताओं की भी जानकारी दें।

(ख) चूंकि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है इसलिए ओसीएलएस द्वारा लागत निर्धारण तत्वों / पद्धति का प्रावधान करने को आदेशित करने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) ओसीएलएस को ट्राई को विश्वास में लेकर केबल लैंडिंग स्टेशन के विभिन्न लागत तत्वों की घोषणा करने के लिए कहा जाए।

2.16.2 सह-स्थान और एक्सेस के लिए प्रभारों को पहले केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी संगत लागत के आधार पर निर्धारित करे और बाद में उसे लागत संघटकों, लागत निर्धारित पद्धति और परिकलन पत्र संबंधी चिंताओं की जानकारी के साथ ट्राई को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे। ओसीएलएस द्वारा लागत निर्धारण अवयवों और अपनायी गई पद्धति का ब्यौरा दिए बिना, ट्राई के

लिए इन प्रभारों का आंकलन करना और उसे अनुमोदित करना बहुत ही मुश्किल होगा। एक्सेस सरलीकरण प्रभार नई एक्सेस व्यवस्था की गैर आवर्ती आरम्भिक लागत पर आधारित है जिसमें निर्माण लागत उपकरण और ऐसे प्रबंधों के लिए विशिष्ट कास कनेक्शन एक्सेस आदि तत्व शामिल हैं। इसी प्रकार, सह स्थान लागत में आवर्ती किराया प्रचालन और भवन की रख रखाव लागत अनुरक्षण, लीज होल्ड, विद्युत और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। ये लागत विशेष रूप से प्रत्येक एक्सेस प्रबंध अथवा सह स्थान सुविधाओं के लिए हैं और इसलिए प्राधिकरण का यह मत है कि ओसीएलएस, इन विनियमों में विभिन्न उपबंधों के अनुसार सीएलएस - आर आई ओ प्रस्तुत करे और इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची और लागत निर्धारण तत्वों, अपनाई गई पद्धति और परिकलन पत्र आदि का भी ब्यौरा हो।

2.17 मुद्दा 16 - सह स्थान सेवा के लिए न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि

2.17.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) (घ) में दिया गया है और तत्पश्चात् निम्नलिखित पैराओं में उन पर विचार किया गया है -

(क) तीन वर्ष की न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि आईटीई के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करके प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और प्रतिस्पर्धा के बीच एक तर्कसंगत संतुलन उपलब्ध कराएगी।

(ख) जब विद्यमान संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा तो प्रतिबद्धता की कोई न्यूनतम अवधि नहीं रहेगी।

(ग) आरंभ में सामान्य अवधि तीन वर्ष हो सकती है और शीघ्र समापन के मामले में छह महीने की सूचना अवधि और सह-स्थान प्रभारों के लिए न्यूनतम एक वर्ष का भुगतान, भले ही वह एक वर्ष की अवधि से पूर्व उस स्थान को खाली कर दे।

(घ) सह स्थान अवधि संदर्भ क्षमता की अवधि के सह - स्थानिक होनी चाहिए। लीज्ड क्षमता के मामले में, संदर्भ क्षमता की अवधि के अनुरूप सह स्थान अवधि का स्वतः विस्तार होने का प्रावधान होना चाहिए।

2.17.2 सह स्थान के मामले में कई बार पात्र आईटीई की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा मात्रा में संसाधनों को सृजित करने की जरूरत पड़ती है। तीन वर्ष की न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और प्रतिस्पर्धा के बीच एक तर्कसंगत संतुलन उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सह स्थान प्रबंध ओसीएलएस को उचित प्राप्तियों के लिए जरूरी एक पर्याप्त अवधि तक किए जाते हों। सामान्यतया संदर्भ क्षमता प्रयोग का अलोप्य अधिकार (आईआरयू) अथवा वार्षिक लीज या लंबे समय तक लीज के आधार पर ली जा रही है, इसलिए सह स्थान वाले पात्र आईटीई ऐसी सुविधाओं के लिए एक निश्चित भविष्य चाहते हैं जब तक कि संदर्भ क्षमता हेतु एक्सेस सरलीकरण के लिए प्रबंध रहे। प्राधिकरण ने यह विचार किया कि चूंकि पात्र आईटीई कुछ वर्षों के लिए आईआरयू आधार अथवा लीज आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्षमता लेंगे, अतः यह वांछनीय है कि सह स्थान के लिए समय विस्तार निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी हो तथा ओसीएलएस द्वारा लागत आधारित प्रभारों का निर्धारण हो और तीन वर्षों की न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि की आरम्भिक लीज पूरी होने पर प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद समय समय पर

प्रकाशित हो। ऐसा ओसीएलएस को भुगतान करने सहित पात्र आईटीई द्वारा किए गए करार के अनुसार सभी दायित्वों को पूरा करने के अध्यक्षीन होगा। प्राधिकरण ने पणधारियों की चिंताओं पर पर्याप्त विचार करने के बाद इन विनियमों में उपयुक्त प्रावधान किए हैं।

2.18 मुद्दा 17 — केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामित्व में बदलाव की स्थिति में समापन

2.18.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त हुई —

समापन में ऐसी स्थितियां शामिल हों जहां पर, यदि सीएलएस कंपनियों का स्वामित्व और सह-स्थान जगह के वास्तविक स्वामित्व में बदलाव होता है तो सीएलएस के करार को करार के अंतर्गत आईआरयू कार्यकाल की शेष अवधि के लिए आईटीई के साथ अपरिवर्तनीय रखा जाएगा और न तो उसे समाप्त किया जाएगा और न ही उसकी निबंधन और शर्तें बदली जाएगी।

2.18.2 लाइसेंस करार में संगत उपबंध को नीचे उद्धृत किया गया है —

“ मैसर्स लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है और जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय है, में है, और जो दूसरे पक्षकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरी (जिसे इसके बाद लाइसेंसी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ में असंगत न हो, को कारोबार, प्रशासकों, परिसमापकों, कानूनी प्रतिनिधियों और स्वीकृत कार्यों में इसका उत्तराधिकारी शामिल है) । श्री के माध्यम से कार्य कर रही है ।

लाइसेंस करार के उपर्युक्त प्रावधान और उत्तराधिकारी के मुद्दे पर लागू अन्य कानूनों के विभिन्न प्रावधान पात्र आईटीई के हित और पणधारियों की चिंताओं की रक्षा करेंगे नई संस्था / निर्दिष्ट/उत्तराधिकारी को ऐसे सभी दायित्वों और देयताओं को पूरा करना होगा । इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि इन विनियमों में इस मुद्दे के विशेष रूप से समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2007

**International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing
Stations Regulations, 2007 (5 of 2007)**

File No. 416-1/2007-F.N.— In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-- (1) These regulations may be called the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. --In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Access Facilitation" means access or interconnection, as the case may be, to the essential facilities (including landing facilities for submarine cable) at cable landing station;

(b) "Access Facilitation Charges" means charges payable by the eligible Indian International Telecommunication Entity to the owner of the cable landing station to interconnect or access the capacity acquired on Indefeasible Right of Use basis or on short-term lease basis from an owner of the submarine cable capacity or a member of consortium owning submarine cable capacity ;

(c) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(d) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(e) "backhaul circuit" means a domestic telecom circuit which connects a cable landing station to the infrastructure or equipment of the eligible Indian International Telecommunication Entity at its premises ;

(f) "cable landing station" means the location,

(i) at which the international submarine cable capacity is connectable to the backhaul circuit;

(ii) at which International submarine cables are available on shore, for accessing international submarine cable capacity; and such location includes buildings containing the onshore end of the submarine cable and equipment for connecting to backhaul circuits;

(g) "Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer" means an offer made by the owner of cable landing station containing the terms and conditions of Access Facilitation and Co-location of equipment (including landing facilities for submarine cables at cable landing stations for connectable system of International submarine cable) published after the approval of the Authority under sub-regulation (4) of regulation 3;

(h) "Co-location Facilities" means the facilities at a submarine cable landing station (including building space, power, environment services, security and site maintenance) which may be offered by the owner of cable landing station to the eligible Indian International Telecommunication Entity to facilitate access to the cable landing station of such owner (including installation of co-location equipment);

(i) "Co-location charges" means the charges payable by the eligible Indian International Telecommunication Entity based on the type of facilities used, for the purpose of housing the equipment of such eligible Indian International Telecommunication Entity, at the premises of owner of cable landing station which provides the access to its cable landing station, and such charges include charges for providing space, power supply, accessing physical facilities, operation and maintenance of co-location site for the said purpose;

(j) "Co-location lead-time" means the time taken by the owner of the cable landing station to make available co-location site to an eligible Indian International Telecommunication Entity;

(k) "Capacity owner" means an International Telecom Carrier or Foreign Carrier or Indian International Long Distance Operator who owns capacity on the international submarine cable landing at the cable landing station in India;

(l) "eligible Indian International Telecommunication Entity" means--

(i) an International Long Distance Operator, holding licence to act as such, and, who has been allowed under the licence to seek access to the

- international submarine cable capacity in submarine cable system landing at the cable landing stations in India; or
- (ii) an Internet Service Provider, holding valid international gateway permission or licence to act as such, and, who has been allowed under the licence to seek access to the International submarine cable capacity in submarine cable system landing at the cable landing stations in India;
- (m) "Grooming Service" means breaking down higher capacity outputs from the submarine cable at a place or point at which it terminates into the lower capacity channels for connection to the backhaul circuits of the eligible Indian International Telecommunication Entity;
- (n) "International Long Distance Operator" means a service provider or operator who has been granted licence to act as such to provide international long distance service;
- (o) "Indefeasible Right of Use" means the right to use the Reference Capacity,
- (i) on long term lease for the period for which the submarine cable remains in effective use;
- (ii) acquired (including equipment, fibers or capacity) under an agreement entered into between the Capacity owner and an eligible Indian International Telecommunication Entity;
- (iii) in respect of which maintenance cost incurred becomes payable in any circumstances during the period of validity of the agreement referred to in sub-clause (i) of this clause;
- (p) "licence" means a licence granted or having effect as if granted under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885, (13 of 1885) and Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933);
- (q) "operation and maintenance charges" means the annual charges,-
- (i) payable to the owner of cable landing station by the eligible Indian International Telecommunication Entity;
- (ii) for operation and maintenance of facilities for accessing the capacity of the cable landing station of such owner;
- (r) "Reference Capacity" means the international submarine cable capacity,--
- (i) in the submarine cable system landing at the cable landing station in India;
- (ii) acquired whether on ownership basis or lease basis by the eligible Indian International Telecommunication Entity;
- (iii) activated by the owner of the submarine cable system or a

member or members of consortium of submarine cable system;

(s) "regulations" means the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007;

(t) "Schedule " means the Schedule appended to these regulations;

(u) " specified international submarine cable" means any submarine cable having International submarine cable capacity landing at a cable landing station in India;

(v) "owner of cable landing station" means a service provider who owns and manages submarine cable landing station in India and has been granted licence to provide international long distance service or Internet service provider;

(w) "Virtual Co-location" means a location—

(i) of the eligible Indian International Telecommunication Entity, being outside the cable landing station, whether adjacent or at a distant from such station;

(ii) at which the eligible Indian International Telecommunication Entity may install its equipment so as to access the sub-marine cable capacity from the cable landing station ;

(x) all other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act and the rules and other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or other regulations, as the case may be.

CHAPTER II

ACCESS TO CABLE LANDING STATION AND RELATED INTERNATIONAL SUBMARINE CABLE CAPACITY

3. Provision of access to cable landing station and related international submarine cable capacity by owner of cable landing station. -----(1)

Every owner of cable landing station shall, in respect of its each cable landing station,---

(a) provide, on fair and non-discriminatory terms and conditions, at its cable landing station, access to any eligible Indian International Telecommunication Entity requesting for accessing international submarine cable capacity on any submarine cable systems;

(b) interconnect specified international submarine cable landing at its cable landing station in India in accordance with the provisions of these regulations;

(c) provide landing facilities for submarine cables at its cable landing station to a service provider, who has been granted licence to act as an International Long Distance Operator under the licence;

(d) submit to the Authority, within thirty days from the date of commencement of these regulations, a document containing the terms and conditions of Access Facilitation and Co-location facilities including landing facilities for submarine cables at its cable landing stations for specified international submarine cable capacity in accordance with the provisions of these regulations (hereinafter referred to as the "Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer") for approval of Authority:

Provided that in case of a cable landing station which comes into existence after commencement of these regulations, the owner of such cable landing station shall submit, on or before the date of coming into existence of such cable landing station, the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer in respect of such cable landing station to the Authority for its approval.

(2) Every Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer including co-location charges shall be prepared in accordance with the Schedule appended to these regulations for submitting the same under sub-regulation (1) to the Authority for its approval.

(3) The Authority shall approve the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer within sixty days from the date of its submission under sub-regulation (1) to the Authority:

Provided that in case the Authority is of the opinion, that the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer requires modifications so as to protect the interests of service providers or consumers of the telecom sector, or to promote or ensure orderly growth of the telecom sector or the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer has not been prepared in accordance with the provisions of these regulations, it may, after giving an opportunity of being heard to the concerned owner of the cable landing station, require such owner to modify the said offer submitted by him and such owner shall make such modifications and submit, within fifteen days of receipt of requirement for the modifications, the said offer after incorporating such modifications, for approval to the Authority.

(4) Every owner of a cable landing station shall publish, on its website and in such other manner as the Authority may specify, within fifteen days from the date of approval of the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer by the Authority, the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer so approved by the Authority and forward a copy thereof to the Authority along with a confirmation to the effect that such offer had been published in accordance with the offer so approved by the Authority and in the manner specified in this sub-regulation.

(5) Every owner of cable landing station, desirous of making any modification

to its Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer published under sub-regulation (4), shall submit all such modifications in such Cable Landing Station-Reference Interconnect offer for prior approval of the Authority.

(6) All the provisions of these regulations, which apply for approval of the Cable Landing Station-Reference Interconnect offer, shall, mutatis mutandis, apply to the modifications to the Cable Landing Station-Reference Interconnect offer approved by the Authority under sub-regulation (3).

4. Application by eligible Indian International Telecommunication Entity for access facilitation to cable landing station and related international submarine cable capacity.----(1) Every eligible Indian International Telecommunication Entity desirous of accessing International submarine cable capacity on any submarine cable systems may make an application, to the owner of cable landing station for Access Facilitation, in the Form specified in Part-I of the Schedule along with the registration fee to be adjusted subsequently against the Access Facilitation Charges payable by such Entity enclosing therewith the following, namely:- ---

(a) a copy of the licence agreement of the eligible Indian International Telecommunication Entity to act as international long distance operator or a copy of licence agreement with valid international gateway permission to act as internet service provider, as the case may be;

(b) a certificate by the eligible Indian International Telecommunication Entity confirming that it has been granted the permission or approval by the Government of India, Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications) for the operation of international gateway or any other authority required, if any under the law;

(c) a confirmation, severally or jointly, from the owner of submarine cable or member of consortium owning Submarine Cable System or capacity owner in the concerned cable system stating that the eligible Indian International Telecommunication Entity has entered into agreement or Memorandum of Understanding with it or them for sale or lease of Reference Capacity.

(d) a certificate by the eligible Indian International Telecommunication Entity confirming that it shall utilise the reference capacity in accordance with the terms and conditions of its licence.

(2) The confirmation referred to in clause (c) of sub-regulation (1) shall, among other things, specify,

(a) the number of units to be acquired or agreed to be acquired, as Indefeasible Right of Use or on annual lease basis, by the eligible Indian International Telecommunication Entity;

(b) the period of lease of the Reference Capacity to be acquired or agreed

to be acquired as Indefeasible Right of Use or on annual lease;

(c) technical information relating to—

(i) slot allocation of Reference Capacity in relevant submarine cable system acquired or agreed to be acquired by the eligible Indian International Telecommunication Entity;

(ii) bearer designation of the capacity acquired or agreed to be acquired;

(iii) the tentative date or likely date of testing of Reference Capacity by the eligible Indian International Telecommunication Entity.

5. Confirmation by the owner of cable landing station after receipt of application under regulation 4.----- (1) Every owner of cable landing station shall, within a period of ten days after receipt of the application for Access Facilitation and the requisite information and documents under regulation 4, send its confirmation of its ability to provide the Access Facilitation and details of required test to be undertaken for providing such Access Facilitation to the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(2) In case it is not feasible due to any valid reason for the owner of cable landing station to comply with the access facilitation procedure or the required test to be undertaken, as the case may be, referred to in sub-regulation (1), such owner shall, within a period of ten days of receipt of the application made under regulation 4, intimate in writing, to the eligible Indian International Telecommunication Entity, an alternative plan for Access Facilitation and required test to be undertaken along with such valid reasons for not complying with such procedure or test.

6. Entering into an agreement for providing Access Facilitation.---- (1) After receipt of confirmation for Access Facilitation, the eligible Indian International Telecommunication Entity shall, within five days from the date of receipt of such confirmation, enter into an Access Facilitation agreement with the owner of the cable landing station:

Provided that in case an International Long Distance Operator or Internet Service Provider, falling under the sub-clause (i) or (ii) of clause (1) of regulation 2, had entered, before commencement of these regulations, into an agreement with an owner of a cable landing station and the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer of such owner has been approved by the Authority under sub-regulation (3) of regulation 3, such owner shall, after publication of the said offer under sub-regulation (4) of regulation 3, give an option to such International Long Distance Operator or Internet Service Provider, as the case may be, to make an application for Access Facilitation in accordance with these regulations.

(2) In case the owner of a cable landing station and the eligible Indian

International Telecommunication Entity fail to enter into an agreement under sub-regulation (1), in that case, both of them, may, jointly, without prejudice to the provisions of section 14A of the Act, at any time, request the Authority to facilitate in the process for entering into the agreement referred to in sub-regulation (1).

(3) Nothing contained in sub-regulation (2) shall be construed to take away any legal right conferred upon the eligible Indian International Telecommunication Entity and the owner of cable landing station under any law for the time being in force and either of them may, at any time during the facilitation process under that sub-regulation, exercise such right conferred upon them under any law for the time being in force.

(4) Nothing contained in sub-regulation (2) shall apply to any matter or issue for which---

(a) any proceedings, before any court or tribunal, or under the Act or any other law for the time being in force, are pending; or

(b) a decree, award or an order has already been passed by any competent court or tribunal or authority, as the case may be.

7. Demand for access to Reference Capacity.----- (1) The eligible Indian International Telecommunication Entity shall, within five days of entering into an agreement under regulation 6, make payment of such fees and charges as specified in the Part II of the Schedule for seeking Access Facilitation for Reference Capacity.

(2) The owner of cable landing station, on receipt of the payment of fees and charges payable under sub-regulation (1), shall consider, the number of units to be acquired or agreed to be acquired as Indefeasible Right of Use or on an annual lease basis as referred to in the agreement, as firm demand made by the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(3) The owner of cable landing station shall, immediately after considering the firm demand referred to in sub-regulation (2), initiate the provisioning of the Access Facilitation for the eligible Indian International Telecommunication Entity.

8. Ensuring provision of backhaul circuit by eligible Indian International Telecommunication Entity.----- (1) Every eligible Indian International Telecommunication Entity shall arrange, within ten days after entering into an agreement under sub-regulation (1) of regulation 6, for backhaul circuit from----

(a) the owner of the cable landing station; or

(b) a service provider who has been granted licence to provide basic service or cellular mobile telephone service or national long distance service, or international long distance service,

so as to make ready the backhaul circuit between cable landing station and

the premises of the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(2) The owner of the cable landing station and the eligible International Telecommunication Entity shall conduct necessary tests as per mutually agreed testing procedure so that the backhaul circuit remains in a state of readiness for interconnection before the tests for Reference Capacity provisioning are carried out.

(3) The owner of the cable landing station shall facilitate the interconnection between the eligible Indian International Telecommunication Entity and the service providers referred to in clauses (a) and (b) of sub-regulation (1) at the cable landing station for provisioning of backhaul circuit under sub-regulation (1).

9. Testing of Reference Capacity proposed to be acquired by eligible Indian International Telecommunication Entity.----- (1) The owner of the cable landing station shall, upon successful testing of the backhaul circuit to the cable landing station, complete all necessary steps for Access Facilitation to the Reference Capacity and such steps shall, *inter alia*, include--

(a) testing of links;

(b) interconnecting the Reference Capacity to the backhaul circuit or equipment of the service providers co-located at the cable landing station of such owner or at a Virtual Co-location.

(2) The owner of cable landing station and the eligible Indian International Telecommunication Entity, being an applicant under regulation 4, shall conduct necessary tests, as per the testing procedure for the provisioning of Reference Capacity from cable landing station in India to distant end or the other country's submarine cable station, within ten days or as may be mutually agreed upon by them.

(3) The owner of the cable landing station shall--

(a) send an intimation, after taking steps referred to in sub-regulation (2), to the eligible International Telecommunication Entity for taking control of the Reference Capacity;

(b) deliver, upon receipt of all necessary payments from the eligible International Telecommunication Entity, the Reference Capacity to such Entity immediately but not later than two days after receipt of such payment and declare the Reference Capacity as commissioned.

10. Access Facilitation Charges and payment terms.----- (1) For the purposes of accessing the landing facilities at a cable landing station the Access Facilitation charges as specified in Part II of the Schedule shall be ---

(a) payable by the eligible Indian International Telecommunication Entity to

the owner of the cable landing station;

(b) determined on the basis of the cost of network elements involved in the provision of access and distributed over the complete capacity of the system.

(2) The Access Facilitation arrangement shall, subject to the payment of the operation and maintenance charges by the eligible Indian International Telecommunication Entity to the owner of cable landing station, continue to be in force during the period of the Indefeasible Right of Use or on an annual lease basis, as the case may be.

(3) The owner of cable landing station shall allow the eligible Indian International Telecommunication Entity to provide Grooming Services at cable landing station of such owner.

11. Capacity up-gradation and payment for capacity up-gradation charges by eligible Indian International Telecommunication Entity.----

In case the capacity up-gradation is required to be provided for Access Facilitation to international submarine cable capacity at cable landing station, the owner of the cable landing station shall, on receipt of request for such up-gradation and payment of charges for such up-gradation from the eligible Indian International Telecommunication Entity, being an applicant under regulation 4, facilitate, without prejudice to the provisions of these regulations, the up-gradation as per mutually agreed terms and conditions including time frame for such up-gradation.

12. Cancellation charges.----- (1) In case the eligible Indian International Telecommunication Entity fails to acquire number of units mentioned in clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 4, either due to withdrawing of authorization or rescinding of agreement referred to in regulation 7 or any other reasons, cancellation charge for the units not so acquired shall be payable by such eligible Indian International Telecommunication Entity to the owner of the cable landing station.

(2) The cancellation charges referred to in sub-regulation (1) shall be such as are specified in Part-II of the Schedule.

13. Termination or discontinuance of Access Facilitation by owner of cable landing station..... (1) The Access Facilitation shall be terminated by the owner of cable landing station----

(a) if the eligible Indian International Telecommunication Entity ceases to hold valid licence either by way of termination or suspension;

(b) in case the arrangement to acquire Reference Capacity on the Indefeasible Right of Use or on an annual lease basis, as the case may be, by the eligible Indian International Telecommunication Entity from submarine cable system owner or a member of the submarine cable system consortium or from concerned cable consortium, is terminated.

(2) In case the annual operation and maintenance charges due and payable

by the eligible Indian International Telecommunication Entity remain unpaid for more than fifteen days from the date such charges became payable, the owner of cable landing station may discontinue the Access Facilitation provided to eligible Indian International Telecommunication Entity after giving a notice, in writing, of not less than fifteen days, of such discontinuance to the eligible Indian International Telecommunication Entity and Access Facilitation shall be restored immediately after due payment of such charges by the eligible Indian International Telecommunication Entity.

14. Restoration of Access Facilities.----- (1) In case the licence of the eligible Indian International Telecommunication Entity has been terminated or suspended but the same is subsequently restored, the Access Facilitation arrangement if discontinued due to such termination or suspension under regulation 13 may be restored by the owner of cable landing station upon payment of all costs incurred by the owner of cable landing station for the purposes of reconnection or restoration of the Access Facilities, as the case may be, by the eligible Indian International Telecommunication Entity to the owner of cable landing station and such reconnection or restoration charges shall be such as may be mutually agreed upon between them or failing which in accordance with the costs specified in Part - II of the Schedule.

(2) If an authorization of the eligible Indian International Telecommunication Entity or arrangement entered into by it to acquire Reference Capacity on Indefeasible Right of Use or lease from submarine cable system or from a member of the submarine cable system consortium or from concerned submarine cable consortium, has been earlier withdrawn or rescinded but is subsequently restored, the access facilitation arrangement, if discontinued due to such withdrawal or rescinding may be restored by the owner of cable landing station upon payment of all costs incurred by owner of cable landing station for the purpose of reconnection or restoration, as the case may be, by the eligible Indian International Telecommunication Entity to owner of cable landing station and such reconnection or restoration charges shall be such as may be mutually agreed upon them or failing which in accordance with the costs specified in Part - II of the Schedule.

CHAPTER III

CO-LOCATION SITE AND CO-LOCATION SPACE

15. Application by eligible Indian International Telecommunication Entity for provisioning of Co-location space.---- (1) Every eligible Indian International Telecommunication Entity, who makes an application for accessing international submarine cable capacity on any submarine cable systems under regulation 4, shall make, simultaneously, another application to the owner of cable landing station in the Form specified in Part -IV of the Schedule for Co-location space at a cable landing station, if such Co-location space is required by it for accessing international submarine cable capacity on any submarine cable system from the owner of

such cable landing station, enclosing therewith the following, namely:-

- (a) equipment layout plan at the Co-location site at which Co-location space is requested for;
- (b) purpose of accessing submarine cable capacity;
- (c) details of Co-location equipment proposed to be installed;
- (d) the details of space and power requirements;
- (e) the floor loading of the Co-location equipment;
- (f) the specification of the Transmission Tie-Cable required;
- (g) the type of optical fibre cable to be used;
- (h) the address, phone number, fax and e-mail of the eligible Indian International Telecommunication Entity at which communications may be sent by the owner of the cable landing station;
- (i) any other requirement for Co-location of equipment.

(2) The owner of the cable landing station shall, within ten days after receipt of the application made under sub-regulation (1), acknowledge the receipt and communicate the acceptance or rejection thereof to the requesting eligible Indian International Telecommunication Entity referred to in sub-regulation (1).

(3) In case it is not feasible, due to any valid reasons, for the owner of cable landing station to provide co-location at the cable landing station referred to in sub-regulation (1), such owner shall, within a period of ten days, of receipt of the application made under sub-regulation (1), intimate in writing such non-feasibility along with valid reasons therefor, to the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(4) The owner of the cable landing station shall reject the application made by the eligible Indian International Telecommunication Entity under sub-regulation (1) if it is not an eligible Indian International Telecommunication Entity or it has not been granted international gateway permission or licence.

(5) After receipt of acceptance from the owner of cable landing station under sub-regulation (2), the eligible Indian International Telecommunication Entity shall, within five days from the date of receipt of such conformation, enter into a Co-location Lease agreement with the owner of the cable landing station.

16. Co-location charges and payment terms.----- (1) The Co-location charges shall be payable, by the eligible Indian International Telecommunication Entity who has been provided Co-location by the owner

of cable landing station, to such owner of the cable landing station within five days of entering into an agreement under sub-regulation (5) of regulation 15.

(2) The Co-location charges referred to in sub-regulation (1) shall be such as had been included in the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer published under sub-regulation (4) of regulation 3 :

Provided that the Authority may specify, by other regulation made by it under the Act, such Co-location charges which shall be payable by a class or classes of eligible Indian International Telecommunication Entity and in such case the approval of the Co-location charges, as specified in Part II of the Schedule by the Authority shall not be required to be obtained under these regulations.

(3) Notwithstanding the time period for provision of co-location services specified under sub-para B of Part-III of the Schedule approved by the Authority, the Co-location charges shall be payable by the eligible Indian International Telecommunication Entity as per time schedule as may be mutually agreed upon by them and where no such time schedule has been agreed upon, the Co-location charges shall be payable within such time period as specified in sub-regulation (1).

(4) The owner of cable landing station shall, upon receipt of application under regulation (1) of regulation 15 and receipt of all charges and fulfillment of other requirements under these regulations, provide the Co-location facility at the cable landing station to the Indian International Telecommunication Entity who made such application.

17. Allocation of alternative Co-location space.----- (1) In case the owner of cable landing station is unable to offer, due to space limitations or any other valid reason, the physical Co-location requested for by the eligible Indian International Telecommunication Entity, the owner of the cable landing station shall take reasonable measures to give an options of virtual Co-location to enable such eligible Indian International Telecommunication Entity to have Access Facilitation:

Provided that in case the owner of cable landing station is unable to offer Co-location space at cable landing station and the eligible Indian International Telecommunication Entity fails to arrange a Virtual Co-location site, then the owner of cable landing station shall endeavour to provide an alternate site other than the Virtual Co-location.

(2) The charges relating to alternate site for Co-location and interconnecting link to the cable landing station shall be borne by the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(3) In case an eligible Indian International Telecommunication Entity is offered, due to space constraints at cable landing station or any other valid technical reason, a Virtual Co-location facility by the owner of the cable

landing station, in that case the owner of the cable landing station shall make available required elements including duct within the building for the purpose of running an interconnection cable within the cable landing station for which the charges shall be payable and borne by eligible Indian International Telecommunication Entity.

(4) The eligible Indian International Telecommunication Entity shall arrange the telecommunication link from Virtual Co-location Site to cable landing station, cost of which shall be borne by such eligible Indian International Telecommunication Entity.

18. Additional Co-location space and Co-location equipment.----- (1) If the eligible Indian International Telecommunication Entity intends to replace, modify or re arrange any of its Co-location equipments in the Co-location space or install additional Co-location equipment in the Co-location space, it shall submit a request in writing to the owner of cable landing station for such modification, rearrangement or additional Co-location equipment or replacement, as the case may be and owner of cable landing station shall intimate, within ten days of receipt of such request, its decision for such replacement, modification or re-arrangement.

(2) The eligible Indian International Telecommunication Entity shall, upon receipt of acceptance from the owner of cable landing station for such request made under sub-regulation (1), modify, rearrange or replace, as the case may be, any of its Co-location equipments in the Co-location space or install additional Co-location equipment in the Co-location space after making payment of all charges and fulfillment of other requirements under these regulations.

19. Installation of Co-location Equipment by eligible Indian International Telecommunication Entity.----- The eligible Indian International Telecommunication Entity, which has entered into an agreement under sub-regulation (5) of regulation 15 with the owner of cable landing station shall install its Co-location equipment in the Co-location space as may be mutually agreed upon between him and the owner of cable landing station, in accordance with the Co-location equipment installation and maintenance procedures specified in Part -V of the Schedule.

20. Authorization for physical access for Co-location space at cable landing station.----- If the application made by the eligible Indian International Telecommunication Entity under sub-regulation (1) of regulation 15 has been accepted by the owner of the cable landing station, the eligible Indian International Telecommunication Entity shall communicate, the names of its personnel in the Form specified in the Part-VII of Schedule to the owner of cable landing station who shall allow them access to the Co-location space and issue the authorization for physical access in the Form specified in the Part-VI of the Schedule.

21. Prohibition to sub-lease the Co-location space.----- The eligible Indian International Telecommunication Entity shall not assign the lease in

respect of or sub-let the Co-location space at the cable landing station and Co-location site.

22. The Co-location space to be used for the purpose of accessing submarine cable capacity in the cable landing station by the eligible Indian International Telecommunication Entity.----- (1) The Co-location space shall be used by the eligible Indian International Telecommunication Entity for the purpose of accessing submarine cable capacity in the cable landing station.

(2) The equipment of the eligible Indian International Telecommunication Entity installed at the Co-location space may be used for, ----

(a) interconnections amongst eligible Indian International Telecommunication Entities and backhaul circuit providers referred to in sub-regulation (1) of regulation 8 at the cable landing station for provisioning of backhaul circuit;

(b) extending the Reference Capacity to the Point of Presence or premises of eligible Indian International Telecommunication Entity.

23. Termination of lease of Co-location space.----- (1) The owner of cable landing station may, in the event of closure of Co-location site or the expiry of the lease of Reference Capacity, terminate the lease of Co-location space, after giving to the eligible Indian International Telecommunication Entity a notice, in writing, of not less than six months from such closure or before the expiry of the lease of Reference Capacity, as the case may be, and such termination of the lease of co-location space shall take effect from the date specified in the notice.

(2) The owner of cable landing station may terminate the lease of Co-location space, if-----

(a) the eligible Indian International Telecommunication Entity ceases to hold valid licence or the licensor directs, in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or for any other reason, the termination of such lease;

(b) the eligible Indian International Telecommunication Entity uses or allows to be used the Co-location space in contravention of the regulations or directions issued under the Act or any other law for the time being in force or in contravention of the terms of the licence;

(c) the eligible Indian International Telecommunication Entity removes or abandons its Co-location equipments or keeps such space idle for a period of more than ninety days;

(d) the Co-location space has become unsafe or unsuitable for the purpose of accessing facilities under these regulations:

Provided that the owner of cable landing station shall not terminate the lease of Co-location space under clauses (b) to (d) unless a notice of not less than ten days had been given to the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(3) Upon termination of the lease of Co-location space on request by the eligible Indian International Telecommunication Entity, prior to the expiry of the lease term, the following charges shall be payable by the eligible Indian International Telecommunication Entity, namely:-

(a) Co-location charges payable for a period not exceeding six months;

(b) outstanding pro-rata site preparation work charges.

(4) Subject to the provisions contained in sub-regulation (3), the owner of cable landing station may, at any time, by giving notice of not less than ten days to the eligible Indian International Telecommunication Entity, terminate the lease of Co-location space if the eligible Indian International Telecommunication Entity fails to complete the installation of its Co-location equipment within ninety days.

(5) If the eligible Indian International Telecommunication Entity fails to complete installation of its Co-location equipment due to circumstances beyond its reasonable control, it shall intimate such circumstances to the owner of cable landing station who shall grant an extension of reasonable time for installation of its Co-location equipment to the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(6) If the eligible Indian International Telecommunication Entity, upon termination of the lease under sub-regulation (1), fails to discontinue the use of its Co-location equipment and remove its Co-location equipment under that sub-regulation, the owner of the cable Landing station may remove the Co-location equipment and restore the Co-location site to its original condition.

(7) Upon expiry or termination of the lease of Co-location space of the eligible Indian International Telecommunication Entity, it shall pay to the owner of cable landing station all reasonable costs, connected with the work undertaken for restoration under sub-regulation (6) after removal of co-location equipment (including the disposal of the Co- location equipment).

(8) Upon expiry or termination of the lease of Co-location space of the eligible Indian International Telecommunication Entity, any physical access granted to the Co-location site shall stand withdrawn.

(9) In case the eligible Indian International Telecommunication Entity requires restoration of co-location facilities already terminated, it may make a request to the owner of cable landing station which shall undertake reasonable endeavors and make all efforts to get the co-location facilities restored to the eligible Indian International Telecommunication Entity, at the

earliest.

(10) Nothing contained in these regulations shall be construed as binding the owner of cable landing station for any service guarantee agreement or any representation by owner of cable landing station on the performance of the specified international submarine cable system.

(11) Without prejudice to the rights of the owner of the cable landing station specified in sub-regulation (2), the eligible Indian International Telecommunication Entity may negotiate with the owner of submarine cable system or Member of the Consortium of submarine cable system, as the case may be, for any restoration arrangement including alternate transmission medium, if necessary.

CHAPTER IV

MISCELLENEOUS

24. No obligation of owner of cable landing station to place Co-location equipment of the eligible Indian International Telecommunication Entity adjacent to each other.----- Every owner of the cable landing station shall endeavor to accommodate any reasonable request by the eligible Indian International Telecommunication Entity for adjacent placement of its Co-location equipment adjacent to each other but such request shall not confer any right upon the eligible Indian International Telecommunication Entity for adjacent placement of its Co-location equipment and the Co-location space allocated and the actual placement of the Co-location equipment as determined by the owner of the cable landing station shall be final.

25. Period of Co-location agreement.----- (1) The agreement between the parties regarding each Co-location space to be leased under the Co-location frame work shall commence on the date the eligible Indian International Telecommunication Entity confirms its acceptance of the charges for the Co-location site and makes payment therefor and remain in force for a minimum period of three years after such commencement or for such period as may be mutually agreed upon between the parties.

(2) The period of Co-location facility referred to sub-regulation (1) shall be renewed by the owner of cable landing station if the eligible Indian International Telecommunication Entity has not defaulted in payment of co-location charges or has not committed any breach of the terms and conditions of such agreement.

26. Reporting Requirements.----- The Access Facilitation agreement entered under regulation 6 or Co-location Lease agreement entered under sub-regulation (5) of regulation 15 or every other agreements entered into in pursuance of the provisions of these regulations between owner of cable landing station and eligible Indian International Telecommunication Entity shall be submitted to the Authority for registration within 15 days from the date of entering into such agreements.

SCHEDULE**FORM OF CABLE LANDING STATION-REFERENCE
INTERCONNECT OFFER (CLS-RIO)**

(See regulation 3 of International Telecommunication Access to
Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007)

PART-I**Form of application for request to Access Facilitation at Cable
Landing Station for International Submarine Cable Capacity**

(See regulation 4)

M/s(Name of eligible Indian International
Telecommunication Entity) hereby request for Access Facilitation to
below mentioned Reference Capacity, which is subject to the Terms and
Conditions published in "Cable Landing Station-Reference Interconnect
Offer (CLS-RIO) made under the provisions of the International
Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing
Stations Regulations, 2007 for Access Facilitation to essential facilities
including landing facilities for submarine cables at cable landing stations
for International submarine cable capacity at cable landing station.

M/sfurnish the necessary details as
follows:-

1. Name of the company and its Address	
2. Billing address	
3. Contact person 3.1 Name: 3.2 Phone No: 3.3 Email: 3.4 Fax:	
4. Particulars of eligible Indian International Telecommunication Entity, being Access Seeker:	
4.1 International Long Distance Operator	
4.2 Internet Service Provider	

4.3 Licence number:	
4.4 Date of issue of Licence (Please attach an attested copy of licence and valid International gateway permission as applicable)	
5. Technical details of Reference Capacity (Please provide or enclose the relevant information and details, as the case may be)	
5.1 Reference Capacity details: Speed (STM-1/STM-4/STM-16/ STM-64 etc.)	
5.2 Number of capacity units	
5.3 Indefeasible Right of Use or Lease	
5.4 Period (in case of Lease)	
6. Technical details of Reference Capacity of submarine cable:	
6.1 Cable Station Backhaul Port details (capacity and type-STM-1e/ STM-1o/STM-4/ STM-16/STM64 etc.)	
6.2 Assignment provided by submarine cable system capacity owner to be attached if available (slot or Fiber Pair allocation in submarine cable, Bearer Designation, Cable System Owner Internal ID etc.)	
6.3 Proposed/tentative date of testing of backhaul circuit	
6.4 Proposed test schedule and copy of work-order/document issued by owner of cable system along with any other related technical information to facilitate planning of Reference Capacity testing.	
6.5 End to end testing (between the station of eligible Indian International Telecommunication Entity and distant end submarine cable station) schedule and provisioning of access of the Reference Capacity at cable landing station.	

7. Details of Reference Capacity owner(s)/submarine cable capacity owner(s) (See clause (c) under sub-regulation (1) of regulation 4)	
7.1 Name of the company and address	
7.2 Contact person 7.2.1 Name: 7.2.2 Phone: 7.2.3 Email: 7.2.4 Fax:	
8. Details of backhaul circuit provider(s) (Domestic Link including local loop)	
8.1 Name of the company and address	
8.2 Contact person 8.2.1 Name: 8.2.2 Phone: 8.2.3 Email: 8.2.4 Fax:	
9. Registration fee payment details 9.1 Cheque/Banker's Cheque/Demand Draft No. _____ dated _____ for Rs . _____ Drawn on (bank/branch) _____	
10. Name of authorized signatory of this form (Please attach authorization)	
11. Any other details required to be given but not specified at serial numbers 1 to 10 of this Form.	

AUTHORIZED SIGNATORY

Date: _____

Name: _____

Signature: _____

Official Seal:

PART - II

(See regulations 3, 7, 10, 12, 14 and 16)

Details of Charges		Amount payable (Rupees)
(1)		(2)
1. Access Facilitation Charges for eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker		
1.1 In case of Indefeasible Rights of Use, one time Access Facilitation Charges per unit capacity payable on execution of the Access Facilitation agreement		
Sl.No.	Per Unit Capacity	
(i)	STM-1	
(ii)	STM-4	
(iii)	STM-16	
(iv)	STM-64	
1.2 In case of lease, recurrent Access Facilitation Charges per annum per unit capacity payable on execution of the Access Facilitation agreement and thereafter before the due date (anniversary of commissioning date) each year subsequently. (applicable only for first three years or period as applicable for each unit capacity)		
Sl.No.	Per Unit Capacity	
(i)	STM-1	
(ii)	STM-4	
(iii)	STM-16	
(iv)	STM-64	
2. Annual Operation & Maintenance (O&M) charges for eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker		
2.1 Charges per annum per unit payable on the execution of the Access Facilitation agreement and thereafter before the due date (anniversary of commissioning date) each subsequent year.		
Sl.No.	Per Unit Capacity	
(i)	STM-1	
(ii)	STM-4	
(iii)	STM-16	
(iv)	STM-64	

3. Restoration charges one time per unit capacity in the event of termination or discontinuance of access facilities		
Sl.No.	Per unit capacity	
(i)	STM-1	
(ii)	STM-4	
(iii)	STM-16	
(iv)	STM-64	
4. Co-location charges: (Please specify the items and their charges separately i.e. building space charges per sq feet, duct & cable runway charges, distribution frame, AC power including standby AC Power, DC power, air conditioning including other physical / environmental services, security and site maintenance etc)		
5. Cancellation charges for eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker (See Regulation 12)		
Sl.No.	Per Unit Capacity	
(i)	STM-1	
(ii)	STM-4	
(iii)	STM-16	
(iv)	STM-64	
6. Any other charges or details for eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker but not specified at serial numbers 1 to 5 of this Form		

Note: The owner of cable landing station shall provide to the Authority, the costing elements considered, their costs and costing methodology employed along with calculations sheet in arriving at the charges submitted above in Part-II of the Schedule of these regulations for international submarine cable capacity access and co-location facilities etc., while submitting the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer as per clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 3.

PART - III**TIME PERIOD FOR PROVISION OF ACCESS FACILITATION SERVICES AND CO-LOCATION SERVICES BY OWNER OF CABLE LANDING STATION**

(See regulation 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 and 16)

Activity (1)	Days (Time limit)
A. TIME PERIOD FOR PROVISION OF ACCESS FACILITATION SERVICES	
1. Eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker submits request to owner of cable landing station	Day 1
2. Owner of cable landing station checks feasibility and reverts to eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker with acceptance or modified schedule for access facilitation and testing; provides proforma for invoice	Day 11 (max 10 days)
3. Date of firm demand: (x is the time taken by of eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker to sign the Access Facilitation agreement including the payment as per invoice); x is the time limit max 5 days as per clause (a) and also 5 days as per clause (b) below:-	Day 11+x
(a) Time limit for Access Facilitation agreement by eligible Indian International Telecommunication Entity	5 days
(b) Time limit for payment as per invoice by eligible Indian International Telecommunication Entity	5 days
4. Eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker arranges and provides backhaul (y is the time taken by eligible Indian International Telecommunication Entity to arrange and provide the backhaul circuit); y is the time limit max 10 days as per clause (a) below:-	Day 11+x+y
(a) Time limit for eligible Indian International Telecommunication Entity to arrange for backhaul circuit from any of the service providers including cable landing stations owner having backhaul circuit capacity at the cable landing station	10 days

5. Owner of cable landing station Cable Landing Station to complete all actions with a view to facilitate access to reference capacity	Day 22+x+y (max 10 days)
6. Owner of cable landing station extend Reference Capacity to cable landing station and provide cross connection immediately but not more than 2 days after completion of step 5.	Day 22/24 +x+y (max 2 days)
7. Any other details required to be given but not specified at serial numbers 1 to 6 of the Para A of this Form	
B. TIME PERIOD FOR PROVISION OF CO-LOCATION SERVICES	
1. Eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker submits Request to owner of cable landing station	Day 1
2. Owner of cable landing station checks feasibility and reverts to eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker with acceptance or rejection with reasons and with alternative proposal	Day 11 (max 10 days)
3. Owner of cable landing station provides provision of Co-location at cable landing station (z is the time taken by of eligible Indian International Telecommunication Entity, being Access Seeker to sign the co-location agreement and payment of charges); Z is the time limit max 5 days as per clause (a) and also 5 days as per clause (b) below:-	Day 12+z
(a) Time limit for the co-location agreement by eligible Indian International Telecommunication Entity	5 days
(b) Time limit for payment of charges for Co-location by eligible Indian International Telecommunication Entity	5 days
4. Any other details required to be given but not specified at serial numbers 1 to 3 of the Para B of this Form	

PART-IV**Form of Request for Co-Location Facility and Services**

(See regulation 15)

Application for Request to Co-location Facility at Cable Landing Station for International Submarine Cable Capacity

M/s(Name of access seeker) hereby request for Co-location facility, which is subject to the terms and conditions published in "Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer (CLS-RIO) made under the provisions of the Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations regulations, 2007.

M/sfurnish the necessary details as follows.

1. Name of the company and its address	
2. Billing address	
3. Contact person 3.1 Name: 3.2 Phone No: 3.3 Email: 3.4 Fax:	
4. Particulars of eligible Indian International Telecommunication Entity, being Access Seeker:	
4.1 International Long Distance Operator	
4.2 Internet Service Provider	
4.3 Licence number:	
4.4 Date of issue of Licence	

5. Details of eligible Indian International Telecommunication Entity requesting for Co-location			
5.1 Date of application			
5.2 Application reference No.			
5.3 Approval for physical access is sought for the purpose of:			
5.4 Reference date /time of access			
5.5 Estimated duration of access			
5.6 Name of Person(s) for which physical access is required	No	Name of Person	Contact No.
	1		
	2		
	3		
	4		
5.7 The Co-location site at which Co-location space is requested:			
5.8 Purpose of accessing submarine cable capacity:			
5.9 Co-location equipment proposed to be installed:			
5.10 The space and power requirements:			
5.11 The floor loading of the Co-location equipment:			
5.12 The capacity of the Transmission Tie-Cable required:			
5.13 The type of optical fibre cable to be used:			

6. On Behalf of eligible Indian International Telecommunication Entity	
6.1 Name:	
6.2 Designation	
6.3 Contact Number	
6.4 Fax Number	
6.5 e-mail id	
6.6 Company Seal	
6.7 Signature	
7. Owner of Cable Landing Stations' (Name) reply to the requesting eligible Indian International Telecommunication Entity	
7.1 Application returned – incomplete / illegible	
7.2 Not approved	
7.3 Reasons for rejection	
8. Approved subject to details & conditions given in the attached letter of authorization	
8.1 Alternative date & time	
8.2 Alternative co-location site (if applicable)	
8.3 Owner of cable landing station approval code	
9. On Behalf of owner of cable landing station	
9.1 Name	
9.2 Designation	
9.3 Contact number	
9.4 e-mail id	
9.5 Fax No.	

9.6 Company seal	
9.7 Signature	

PART-V**CO-LOCATION EQUIPMENT INSTALLATION AND MAINTENANCE
GUIDELINES****(See regulation 19)****1. INSTALLATION OF EQUIPMENT AT CO-LOCATION SPACE****1.1 Installation of Co-location equipment**

- (a) Prior to commencing installation of its Co-location equipment, the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker must submit detailed installation plans and installation schedule.
- (b) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must ensure that the floor loading of its Co-located equipment shall be limited to as specified by owner of cable landing station. The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker shall certify that the floor loading limit will not exceed as specified.
- (c) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker must install its Co-location equipment in the Co-location space within ninety days after the final site inspection or as mutually agreed. If the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, failure to complete installation is attributable to circumstances beyond the reasonable control of eligible Indian International Telecommunication Entity, owner of cable landing station will grant a reasonable extension of time for installation to the eligible Indian International Telecommunication Entity, at his request. Eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, request under this clause must describe the circumstances beyond its control and such request must be received prior to the expiry of the aforementioned ninety days period.
- (d) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker must not locate equipment other than Co-location equipment in the Co-location space.

1.2 Optical Fibre Cable

Unless otherwise agreed by the parties, the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must not install more than two physical optical fibre cables in the Co-location space and up to the lead-in manhole outside Co-location space.

1.3 Power & Earth

Owner of cable landing station shall, if the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker so desires, designate and provide the Exchange Earth and Power Distribution Point for the eligible Indian International Telecommunication Entity. The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, shall pay owner of cable landing station the charges for the provision of the Exchange Earth and power installation and termination in accordance with owner of cable landing station published Co-location charges.

1.4 Interference

Each Party shall ensure that its Co-location equipment does not cause any interference to the other Party's equipment, plant, facilities, Networks and the equipment of other occupying eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, in the Co-location space, including when installing equipment. In the event of any interference, the parties shall take in good faith reasonable measures to resolve the problem promptly. Where the eligible Indian International Telecommunication Entity's equipment is causing interference to existing equipment and the interference cannot be resolved, the eligible Indian International Telecommunication Entity shall remove the source of interference immediately.

1.5 Standard Operating Procedures and Safety

(a) Regarding the installation, operation and maintenance of its Co-located equipment located in the Co-location space, the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must comply with owner of cable landing station Standard Operating Procedures for Co-location space and any written instructions, which are provided to the eligible Indian International Telecommunication Entity by owner of cable landing station.

(b) Regarding the physical access to the Co-location space, the eligible Indian International Telecommunication Entity shall comply with owner of cable landing station Standard Physical Access Procedures as amended from time to time and any written instructions, which are provided to the eligible Indian International Telecommunication Entity by owner of cable landing station.

(c) Owner of cable landing station will get the Co-location space inspected by its representatives/staff to which access has been approved for the installation, modification, replacement or addition of the equipment to verify that the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, is undertaking the installation, modification, maintenance, operation, replacement or addition of the equipment in accordance with the plan and such other written instructions provided to the eligible Indian International Telecommunication Entity.

(d) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, shall consult with and obtain the consent of owner of cable landing station before carrying out any hacking or drilling work on the floor, wall and ceiling slabs.

(e) No work shall be performed by the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, on any of equipment, facilities, plant or Networks including, but not limited to earth bars and Power Distribution Points/boards of the owner of cable landing station.

(f) Owner of cable landing station staff shall carry out all the interconnection of the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, Co-location equipment to owner of cable landing station earth bars and Power Distribution Points/boards. Charges for the work shall be borne by the eligible Indian International Telecommunication Entity, as set out in owner of cable landing station published Co-location charges.

(g) Where, during the course of installation, operation, maintenance, replacement or repair of its Co-located equipment the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, causes any damage to owner of cable landing station Co-location site, plant, network, equipment or facilities, the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must report the damage immediately to owner of cable landing station. Owner of Cable Landing Station shall rectify the damage in any way it deems fit, the cost and expense thereof shall be borne by the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker.

1.6 Final Inspection

(a) Upon completion of the installation of the Co-location equipment in the Co-location space, the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, shall advise owner of cable landing station and request owner of cable landing station to

conduct a final inspection and confirm that the installation conforms to the approved detailed installation plans.

(b) Where the final inspection reveals that the installation does not materially conform to the approved detailed installation plans, owner of cable landing station shall notify the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker. The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker must reinstall or take other appropriate corrective action within ten (10) working days of notification, or such other time as is otherwise agreed.

(c) If the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, fails to reinstall or take the appropriate corrective action referred to in clause 1.6(b) above, the owner of cable landing station may take appropriate corrective action including removal of the eligible Indian International Telecommunication Entity's Co-location equipment. The reasonable costs for the corrective action shall be borne by the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker.

2. MAINTENANCE OF CO-LOCATION EQUIPMENT IN CO-LOCATION SPACE

2.1 The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, shall be responsible for the operation and maintenance of its Co-location equipment or as mutually agreed with the owner of cable landing station.

2.2 If a fault, defect or problem with the Co-location equipment of the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, causes damage to the Co-location space or facilities of the owner of cable landing station, the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker must:

- (a) notify owner of cable landing station as soon as practicable; and
- (b) repair the fault, defect or problem or take other appropriate corrective action immediately.

2.3 The Co-location equipment must only be used by the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, for the purpose of connecting the eligible Indian International Telecommunication Entity's Network to access Reference Capacity on specified international submarine cable at cable landing station under this Schedule or for interconnection with other service providers' equipment/ network located in cable landing station for provisioning of backhaul circuit.

2.4 Compliance

- (a) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must ensure that its employees, agents and approved sub contractors comply with the provisions of this document including all reasonable procedures and directions of owner of cable landing station as notified from time to time.
- (b) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must comply with all laws, standards, authorizations and leases when performing works.
- (c) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, must ensure that it has all necessary permits, approvals and leases from any person, governmental, regulatory or relevant authority in order to perform works or provide service.
- d) The eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, will vests no right, title or proprietary interest in the Co-location site.

2.5 Marking of Equipment

The Co-location equipment must be marked by the eligible Indian International Telecommunication Entity, being access seeker, to clearly indicate that it is leased by the eligible Indian International Telecommunication Entity, and in such manner as owner of cable landing station may reasonably direct.

PART - VI

Form of Letter of Authorization for Physical Access to Co-Location Space

(See regulation 20)

This Letter of Authorization is issued in conjunction with the final approval given to the request application via reference _____ date _____

It must be carried in the possession of the designated supervisor/person at all time during the period of access granted to the Co-location space as indicated below

Location of Co-location space granted for access:

[Location / Building name]

Photo identity

1. Approved date of access

2. Approved time of access
3. Approved duration of access

On behalf of owner of cable landing station

Signature

Name

Contact phone number.....

Fax No.....

PART - VII

Form of Name and Details of Personnel to be Authorized

(See regulation 20)

S.No.	Name of the Persons/ Representatives/ Contractor of eligible Indian International Telecommunication Entity (access seeker)	Identity Card No.	Contact Tel. No.	Fax No.
1				
2				
3				
4				
5				

R. K. ARNOLD, Secy.
[ADVT-III/IV/Exty.142/07]

Note : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007 (5 of 2007).

EXPLANATORY MEMORANDUM**1. BACKGROUND**

1.1 International Private Leased Circuits (IPLC) is one of the significant elements of international connectivity for Internet, Broadband and IP enabled services. The international connectivity consists of distant end IPLC half circuit, near end IPLC half circuit and access to submarine cable landing stations. At the time of opening of the international long distance telecom services to private sector in the year 2002, the Government had realized that submarine cable landing station is essentially a bottleneck facility and the fact that access to international connectivity would be severally influenced by monopolistic position of the incumbent International Long Distance (ILD) operator.

1.2 In order to enhance competition in international connectivity segment, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) initiated a consultation process in June 2005. TRAI made recommendations to Department of Telecommunications (DOT) on measures to promote competition in International Private Leased Circuits in India on December 16, 2005. TRAI's recommendations pertaining to access to essential facilities including landing facilities for submarine cables have been accepted by the licensor. The Department has also amended relevant clauses in ILD licence to enable TRAI to bring out regulations to ensure efficient, transparent and non-discriminatory Access to Essential Facilities (including landing facilities) for submarine cables at Cable Landing Stations.

1.3 The Authority has, thereafter, for the purpose of bringing out regulations to ensure efficient, transparent and non-discriminatory access to Essential Facilities, including landing facilities for submarine cables, at Cable Landing Stations released a Consultation Paper on 13th April, 2007 including the draft regulations with detailed description to various terms & conditions proposed for access facilitation for submarine cables at Cable Landing Station (CLS) and co-location of equipment at CLS. The stakeholders were to submit written comments by the 30th April 2007. On the request of some of the stakeholders, the date for submission of written comments was extended till the 7th May 2007. Written comments were received from AT&T, Orange Business Services, BT Global Services, BSNL, MTNL, Bharti, VSNL, Reliance, Cables & Wireless, Sify Communications Ltd., Verizon Communications Pvt. Ltd., ISPAI, Telxess Consulting Service Pvt. Ltd. and Asia Pacific Carriers' Coalition. Gist of comments received from stakeholders by the extended date of submission of comments i.e. 7th May 2007 was placed on the TRAI's website. Open House Discussion was held on 14th May 2007 in

Delhi with the stakeholders wherein stakeholders had expressed their views on various aspects of the subject.

2. EXAMINATION OF MAIN COMMENTS MADE AND ISSUES RAISED BY STAKEHOLDERS

2.1 The Authority has taken various comments and inputs of the stakeholders into consideration and analysed the matter in detail. For the sake of clarity the comments made and issues raised by stakeholders are given in italics followed by consideration and decision of the Authority on the points.

2.2 ISSUE 1: APPLICABILITY AND NECESSITY OF REGULATION

2.2.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in Paras (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) *The scope of the proposed Regulation should be narrowed to focus on access, co-location and backhaul arrangement at cable landing stations controlled only by dominant operators.*

(b) *CLS-RIO to access the essential facilities and co-location at cable landing stations should be voluntarily published by the concerned landing station operator, and no ex-ante Regulation should be resorted to.*

(c) *Access facilitation Regulation for CLS is urgently required to facilitate access to international capacities as well as co-location facilities at CLS.*

(d) *This Regulation should not extend to mandating landing arrangements for new submarine cables.*

2.2.2 In this matter, the Authority noted that majority of the stakeholders are in favour of mandating access and co-location to submarine cable landing station, which is an essential input for many international telecommunication services. The Authority further noted that limiting the scope of this regulation to mandate access, co-location and backhaul arrangement at cable landing station controlled only by dominant / incumbent operators would not yield the optimum results and will also hinder the emergence of sustainable competitive market. It may also impose burden and obligation only on dominant / incumbent operators to meet request for access and would, therefore, not be fair. The Authority is of the view that adequate competition is not there at present in accessing international bandwidth. Therefore, to create effective competition in the sector, Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer (CLS-RIO) needs to be mandated for the owner of all cable landing stations including those would be commissioned in the future.

2.3 ISSUE 2: TIME FRAME FOR SUBMISSION OF DRAFT CLS-RIO BY OWNER OF NEW CABLE LANDING STATIONS TO THE AUTHORITY

2.3.1 Following comment received on the issue.

Relevant CLS owner should provide the draft RIO terms no less than six months prior to a new cable system being activated.

2.3.2 Submitting the draft CLS-RIO six months prior to commissioning a new cable landing station by owner to the Authority for approval would not be feasible in some of the cases. Discussion with industry suggested that establishing an international cable system in India is a time consuming and complex process involving various clearances including security clearance, maritime clearance and civil authority permission etc. Thus it may not be possible for the owner of the cable landing station to determine the exact date of commissioning of the cable landing station. Therefore, the Authority is of the opinion that it is sufficient that owner of the cable landing station submits its CLS-RIO to the Authority on or before the date of commissioning of the cable landing station.

2.4 ISSUE 3: COMMENT OF OTHER PARTIES ON CLS-RIO SUBMITTED BY OWNER OF CABLE LANDING STATION (OCLS) TO THE AUTHORITY FOR APPROVAL

2.4.1 Following comment received on the issue:

Other parties may wish to comment on the proposed CLS-RIO terms which is submitted to the Authority for approval.

2.4.2 The Authority has noted this point of view of one of the stakeholders and is of the view that this is not relevant and appropriate to seek the comments on the CLS-RIO submitted by the OCLS to the Authority for approval. Since OCLS, while submitting the CLS-RIO, has been mandated to submit the detail of network cost elements and costing methodology adopted to arrive at the charges prescribed in various parts of the CLS-RIO. Therefore, the Authority is of the opinion that seeking comments again of stakeholders may unnecessarily delay the whole process and at the same time adequate opportunity has already been given to stakeholders.

2.5 ISSUE 4: TIME FRAME FOR UPGRADATION

2.5.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in Paras (a) and (b) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) *Any facilitation of upgrade facility should be in accordance with a specified time frame.*

(b) *There is a no provision in the Regulation to mandate the OCLS to upgrade the co-location space in case of non-availability.*

2.5.2 The capacity upgradation to access the submarine cable capacity requires procurement of equipment by the requesting eligible Indian International Telecommunication Entity (ITE) as the entire cost of such upgradation required to be borne by the requesting ITE or foreign submarine cable capacity owner with whom the ITE has entered into an agreement for acquisition of reference capacity. Moreover, basic ingredients of the upgradation to meet the new landing requirement may not be uniformly applicable. Therefore, it would suffice if Owner of Cable Landing Station (OCLS) are mandated to be non-discriminatory and transparent in their charging for upgradation and time frame and it should be best left to mutual negotiations in line with the global practices.

2.6 ISSUE 5: NOTICE BEFORE ACCESS FACILITATION TERMINATION

2.6.1 Following comment received on the issue:

In addition to the 30 days payment period, the CLS owner would be required to give the eligible Indian International Telecommunication Entity (ITE) 14 days prior written notice (with opportunity to rectify the breach) before the CLS owner could terminate the service.

2.6.2 The Authority considered the concern raised by the stakeholders regarding notice before termination and decided that if annual operation and maintenance charges due and payable by the eligible Indian international telecommunication entity remain unpaid for more than 15 days from the date such charges become payable, the owner of cable landing station may discontinue the Access Facilitation provided to the eligible ITE after giving notice, in writing, of not less than 15 days of such discontinuance to the eligible ITE. The Authority is also of the view that by having a notice period before termination, may also avoid the disputes. Moreover, there would be one more advantage by way of notice period to the affected party i.e eligible Indian International Telecommunication entity would be able to rectify the breach and also end consumers will not be affected.

2.7 ISSUE 6: INTERCONNECTION AND MANDATING LEASING OF BACKHAUL FACILITY AT CABLE LANDING STATION FOR PROVISIONING BACKHAUL CIRCUIT

2.7.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in Paras (a) and (b) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) *Regulation should allow interconnection between co-locating ITEs at cable landing station. This would offer the ability for international traffic handoff amongst the ITEs and would offer them access to multiple backhaul service providers within the cable landing station.*

(b) *TRAI should mandate the leasing of backhaul facility by dominant cable station operators for an interim period at cost oriented rates to ensure that competitive ILDOs do not pay unreasonable charges for these services before the development of competitive backhaul services at each cable landing station.*

2.7.2 Mandating leasing of backhaul facility to dominant owner of the cable landing station would discourage any fresh creation of additional backhaul infrastructure. Instead of mandating owner of cable landing station to provide backhaul facility, it is better to provide flexibility to eligible ITE to take backhaul facility from any of the service providers. This will provide more options to eligible ITEs for backhaul facility. The primary objective of this Regulation is to mandate access facilitation for the available international bandwidth and backhaul circuit provisioning be made available at reasonable terms with flexibility.

2.7.3 Interconnection between co-locating ITEs / backhaul service providers at CLS would facilitate the provisioning of backhaul circuit speedily and at competitive rates. Eligible ITE shall also get the benefit of accessing international reference capacity even without placing its own equipment at CLS by utilizing the backhaul circuit capacity of other service providers located there. This would ease the pressure for Co-location space at cable landing station. The other benefit for not mandating OCLS for provisioning of backhaul circuit is that the ITE will get the flexibility of taking backhaul circuits at competitive terms from any of the service provider including the OCLS. Therefore, the Authority has made suitable provision accordingly in these regulations.

2.8 ISSUE 7: CHARGES FOR ACCESS FACILITATION AND OPERATION AND MAINTENANCE TO BE CAPACITY INDEPENDENT

2.8.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in Paras (a) to (b) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

2717 GI/07-11

(a) Charges for cross-connection services should be capacity independent. The annual recurrent access charges available commercially at CLS are levied on a per STM-1 or 155 Mbps of cable capacity. There is a no nexus between the capacity and the cost for service provision.

(b) Charges should be cost-oriented, access facilitation charges, annual operation and maintenance charges and restoration charges should not be structured on a "per unit capacity" basis. Under a cost-oriented fee structure, only access costs that are incurred on a per unit capacity basis should be charged on that basis.

2.8.2 The Authority has provided the basic frame work through Schedule annexed with these regulations for disclosure of charges to be published by OCLS after the approval of the Authority. The Authority would consider these points after owners of the CLSs submit their CLS-RIO for approval with the details of cost of network elements, costing methodology and calculation sheets etc.

2.9 ISSUE 8: SHARING OF SECURITY MONITORING FACILITY

2.9.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in Paras (a) to (c) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) the sharing of security monitoring facilities at CLS with new ILD operators should be mandated.

(b) In the new ILD license conditions there is a provision for sharing of monitoring capabilities under mutual agreement with existing licensees from whom international connectivity is taken to provide layer 2 and layer 3 VPN services. This provision in the license can enable a new ILD operator to start offering the services in a short timeframe without waiting to install its own security monitoring equipment thereby lowering a potential barrier to entry for new operators.

(c) International telecommunication entities that are accessing the capacity from cable landing station, should have their own data & voice monitoring system. The International telecommunication entity should be responsible for all security guidelines, set as per the licensing conditions.

2.9.2 The International Long Distance Operators (ILDOs) are fully responsible to comply with the security conditions imposed on them through the licence conditions. Licensor has already mandated security conditions for ILDOs through ILD licence wherein installation of suitable

monitoring equipment is necessary for the ILDOs. Mandatory access to cable landing station should not dilute any of the security condition which is required as per respective licences. National security is of the great importance, therefore, sharing of security monitoring facility at CLS with eligible ITEs/new ILDOs should be governed as per the respective licences and licensing conditions specified in such regards thereto. Therefore, the Authority is of the opinion that no regulation or mandating provision needed for the issue in these regulations

2.10 ISSUE 9: PRE-APPROVAL OF INTERCONNECT AGREEMENT BY THE TRAI

2.10.1 Following comment received on the issue:

In principle, all agreements between the owner of cable landing station and eligible ITEs pursuant to the CLS-RIO should be pre-approved by TRAI. In this respect, the Access Facilitation Agreement should form part of the pre-approved CLS-RIO. This would avoid any potential delays and stalemate if it were to be commercially negotiated and better achieve timely provision of access to and collocation of essential facilities at Cable Landing Stations.

2.10.2 The Authority is of the opinion that the role of TRAI should be purely on need basis and once the Cable Landing Station - Reference Interconnect Offer (CLS-RIO) is approved by the TRAI and published by OCLS and on the basis of which such Access Facilitation Agreement is made should be adequate. Further to maintain transparency and non-discrimination, it would be appropriate if the interconnect agreement is submitted to the Authority for registration within 15 days from the date of the agreement. Accordingly provision has been made in these regulations.

2.11 ISSUE 10: INTERNATIONAL GATEWAY PERMISSION FOR ISP

2.11.1 Following comment received on the issue:

Eligible ITE such as an ISP with international gateway permission should include both types of permission i.e. submarine cable gateway and / or satellite gateway.

2.11.2 In this regard, it is understood that there is no separate international ISP gateway permission for meeting the Internet bandwidth requirement through International Leased Circuits (IPLCs) provided either through cable landing stations on submarine cable capacity and through satellite earth station on satellite media. The ISPs with International Gateways are fully responsible to comply with the security conditions imposed on them through the licence conditions. Licensor

has already mandated security conditions for ISP through its licence in this regard wherein installation of suitable monitoring equipment and obtaining approval/ permission from Department of Telecommunications (DoT) to operate the ISP International Gateway after security agencies clearance is necessary for it. Therefore, the Authority is of the opinion that if an ISP has the permission and security monitoring facilities to meet the security requirement, it may seek access facilitation being eligible ITE for international reference capacity at the cable landing stations.

2.12 ISSUE 11: APPROVAL OF THE ACCESS AND CO-LOCATION CHARGES

2.12.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below in Paras (a) to (b) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) charges for collocation and access should be determined in the first instance by the cable landing station owner based on the relevant costs and should be submitted to the TRAI for approval with information concerning the underlying cost components. The TRAI should evaluate these charges on the basis of an international benchmarking approach by comparing them with similar charges in other countries.

(b) Cost of real estate, power, human resources, air-conditioning, taxes etc. and also the cost of extending of capacity from CLS to a convenient location for access provisioning may be different from place to place. It would suffice if OCLS are mandated to be non-discriminatory and transparent in their charging.

2.12.2 The Authority examined the principle that whether the cost based charges for access facilitation and co-location charges are required to be prescribed in the regulations or OCLS are mandated to publish non-discriminatory and transparent charges for access facilitation and co-location etc. The Authority observed that in most of the countries the charges are published by the OCLS with the prior approval of the regulator. The Authority is also of the view that to have reasonable and fair charges, the need is to have such charges on cost oriented basis and also to provide first opportunity to the owner of the cable landing station. It is appropriate that OCLS determine the charges on the basis of cost oriented principles taking into account the cost involved in access facilitation, operation & maintenance, cancellation and in provisioning of co-location facilities including Co-location space and submit to the Authority. However, these charges will be approved by the TRAI on the basis of well-established costing methodology already in vogue in the Authority. Prior-approval of the TRAI will ensure transparency, fairness and reasonability and also OCLS will not tend to adopt an arbitrary

approach in prescribing various charges. Therefore, the Authority has made provisions in these regulations to address this issue.

2.13 ISSUE 12: PROVISION FOR COMPLAINTS BEFORE THE AUTHORITY

2.13.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized in Paras (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) *TRAI should also allow ITEs and other international operators to bring complaints before the Authority in the event that cable landing station owners attempt to impede cable station access in any manner, including in ways not anticipated by these regulations.*

(b) *Once this framework is implemented, failing which, either disputing party should be able to call upon TRAI to intervene and provide resolution to the dispute.*

(c) *In the case of dispute the jurisdiction lies with TDSAT.*

(d) *TRAI facilitation is always welcome.*

2.13.2 Dispute resolution mechanism lies with the Hon'ble TDSAT. However, in case of owner of a cable landing station and the eligible Indian International Telecommunication Entity fail to enter an agreement, in that case both of them may jointly, without prejudice to the provisions of the Section 14A of the Act, at any time request the Authority to facilitate in the process of entering into agreement. For effective enforcement and implementation of these regulations or any other regulation made thereto, the Authority may intervene at any time as per the provision of the TRAI Act. Therefore, the Authority is of the opinion that there is no need to make separate provision in these regulations for such complaints. However provision has been made for facilitating the process of entering into agreements if required by parties involved.

2.14 ISSUE 13: PENALTIES

2.14.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized in Paras (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) *Penalties for failure to adhere to mandated time frames are required to be included.*

(b) *the mandate may not come into actual practice in spirit and in words, if there are no provisions for penalties for delay at any step.*

The authority may kindly include suitable and deterrent financial penalties in case of proven delays.

(c) The provisions of the proposed regulation will not be effective in true spirit unless strict penalties are recommended in case of any contravention. Hence, we would like the Authority to implement penalties on both the OCLS and the eligible ITE through appropriate regulations in all cases where the party involved has contravened any of the provisions put forth by this regulation.

(d) Imposing unnecessary or unnecessarily complicated procedures that increase risks of a requesting party's non-compliance (thereby exposing applicant to penalties or to termination of an application)

2.14.2 As per TRAI Act:

"Penalty for contravention of directions of Authority

29. If a person violates directions of the Authority, such person shall be punishable with fine which may extend to one lakh rupees and in case of second or subsequent offence with fine which may extend to two lakh rupees and in the case of continuing contravention with additional fine which may extend to two lakh rupees for every day during which the default continues."

2.14.3 The case of failure to adhere to mandated time frame by the service providers is a violation of the regulation of the TRAI and would be dealt with as per the provisions of TRAI Act. Therefore, the Authority is of the opinion that there is no need to make specific provisions in this regard.

2.15 ISSUE 14: MANDATING ACCESS TO CAPACITY FOR PRIVATE CABLE LANDING IN INDIA

2.15.1 Following comments were received on the issue:

The proposed Regulation may not be effective in case of private cables landing in India. In order to make the proposed Regulation effective in a real sense, the integrated cable owner should be obligated to a must provide Regulation, subject to technical feasibility and availability of the capacity.

2.15.2 The scope of the present regulation is to mandate access to the cable landing station on fair, non-discriminatory and transparent manner. There is no rationale for TRAI to make any such separate provision in these regulations for integrated cable landing station owners having reference capacity for access facilitation. All OCLSs are subjected

to uniformly to these regulations. However, if required at later date that such integrated cable landing station owners are resorting, in access facilitation / provisioning of Co-location facilities, to non-discriminatory and unfair practices than the TRAI would consider appropriate regulatory intervention as per the situation and the circumstances.

2.16 ISSUE 15: WHILE SUBMITTING CLS-RIO, COSTING ELEMENTS AND COSTING METHODOLOGY TO BE PROVIDED TO TRAI

2.16.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized in Paras (a) to (c) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) *Dominant cable landing station owner should submit their proposed charges for access facilitation and co-location to the TRAI for approval with information concerning the underlying cost components.*

(b) *Since there is an adequate competition, there is a no need to mandate provisioning of costing elements / methodology by OCLS.*

(c) *The OCLS may be asked to declare the various cost elements of cable landing station to TRAI in confidence.*

2.16.2 Charges for co-location and access should be determined first by the cable landing station owner based on the relevant cost and should be submitted to the TRAI for approval with information concerning the costs components, costing methodology and calculation sheets. Without having details of the costing elements and methodology adopted by the OCLS it would be very difficult for the TRAI to evaluate these charges and approve the same. Access facilitation charges are based on the non-recurring initial cost of the new access arrangement, including such elements as the cost of construction, equipment and cross-connect access which are specific to such arrangements. Similarly, co-location cost will also comprise the recurring rental and operation and maintenance cost of building support and maintenance, leasehold, power and other utilities. These costs also are specific to each access arrangement or co-location facilities and, therefore, the Authority is of the view that OCLS should submit CLS-RIO as per the various provisions in these regulations and as per the Schedule annexed with these regulations along with the details of costing elements, methodology employed and calculation sheets etc.

2.17 ISSUE 16: MINIMUM COMMITMENT PERIOD FOR CO-LOCATION SERVICE

2.17.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized in Paras (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter.

(a) A minimum commitment period of three years would provide a reasonable balance between the need to encourage the competition, by reducing entry barriers for ITEs.

(b) When the existing resources are utilized there should be no minimum period of commitment.

(c) General term could be three years initially with six months notice period in case of early termination and minimum one year payment of co-location charges even if he vacates before one year period."

(d) A term of co-location should be co-terminus with the term of reference capacity. In case of leased capacity there should be provision for automatic extension of co-location term to match with the term of reference capacity.

2.17.2 In case of Co-location many times the large amount of resources need to be created to fulfill the specific requirements of eligible ITE. A minimum commitment period of three years would provide a reasonable balance between the need to encourage competition and ensure that Co-location arrangement are maintained for a sufficient period necessary for reasonable returns to OCLS. Normally reference capacity is being taken on Indefeasible Right of Use (IRU) or annual lease or on long lease basis, therefore, Co-located eligible ITEs would like to have a certainty for such facilities till the arrangement exist for access facilitation for reference capacity. The Authority considered that since eligible ITE would take international reference capacity on IRU basis or on lease basis for certain number of years, therefore, it would be desirable that extension of the time for Co-location may continue on fair, non-discriminatory, transparent and cost based charges to be determined by OCLS and published after the approval of the Authority from time to time on completion of initial lease of minimum commitment period of three years. This shall also be subject to fulfillment of all obligations as per the agreement made by eligible ITE including payments to OCLS. The Authority, after carefully considering the concerns of stakeholders has incorporated suitable provisions in these regulations.

2.18 ISSUE 17: TERMINATION IN THE EVENT OF CHANGE IN OWNERSHIP OF CABLE LANDING STATION

2.18.1 Comments received on the issue are as follows:

Termination – should include situations where, ownership of CLS companies and physical ownership of Co-Location spaces changes, the agreement of the CLS shall be kept irrevocable with the ITE for the remaining period of the IRU Tenure under the Agreement and shall not discontinued or terms and conditions changed.

2.18.2 The relevant provision in the licence agreement is quoted below:

*“M/s -----
----- LIMITED, a company registered under the Companies
Act 1956, having its registered office at -----
-----,
acting through Shri -----,
authorised signatory (hereinafter called the LICENSEE which
expression shall, unless repugnant to the context, include its
successor in business, administrators, liquidators, legal
representatives and permitted assigns) of the SECOND
PARTY.”*

The above provision in licence agreement and various provisions in other laws in force on the issue of successor will adequately safe guard the interest of eligible ITE and also address the concerns of the stakeholders. The new entity/ assignee/successor will have to fulfill all such obligations and liabilities. Therefore, the Authority is of the opinion that there is no necessity to specifically address this issue in the regulations.